साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 40 03 - 09 अक्तूबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

सामाजिक बुराईयों को दूर करने की आवश्यकता पृष्ठ-6

भारत में शिक्षा का अर्थशास्त्र पृष्ठ-7

भारत एक बार फिर होता जा रहा है
भीड़ हिंसा का शिकार
हमारे हुकमरां आख़िर कब जागेंगे?

भीड़ हिंसा देश की गंगा-जमुनी संस्कृति बिगाड़ने का एक इशारा है जो देश की एकता और अखंडता के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही भीड़ हिंसा की ख़बरों ने एक फिर एक विशेष वर्ग को चिंतित बना दिया है। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के नीमच में एक व्यक्ति को वाहन से बांध कर घसीटा गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसी घटनाओं का दुष्प्रभाव यह पड़ रहा है कि इन पर अंकुश लगने के बजाय इनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता देखा जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देवास, उज्जैन, इंदौर में भीड़ हिंसा की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। उज्जैन के महिदपुर में धार्मिक नारे न लगाने पर दुकानदार का सामान फेंकने और देवास जिले के हाटपिपल्या में आधार कार्ड नहीं दिखाने पर फेरीवाले को पीटने की घटनाएं भी सामने आईं। ये सभी घटनाएं कुछ के अंतराल पर हुई है।

इंदौर का मामला तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था, जिसमें भीड़ एक युवक की पिटाई करती दिखाई दे रही है। यह घटना इंदौर में बाणगंगा क्षेत्र की है, जहां चूड़ी बेचने वाले एक शख़्स को लोगों ने पीट दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया हैं चूड़ी बेचने वाले के ख़िलाफ़ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर पहचान छिपाने के आरोप भी लगे हैं। अब प्रश्न मौक़े परन्याय करती भीड़ पर खड़े होते हैं। अगर वह युवक दोषी है, तो इसकी जांच करने का काम पुलिस और सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है। हमारी व्यवस्था में भीड़ को यह अधिकार किसने दिया कि वह सड़कों पर न्याय करने उतर जाए? सड़कों पर न्याय करती भीड़ ने एक बार फिर व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया और भीड़ हिंसा पर चर्चा को जन्म दिया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'हम' शब्द इस राष्ट्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है, पर जब पालघर जैसी भीड़ हिंसा की घटनाएं होती हैं, तो 'हम' पर प्रश्नचिह्न लग जाते हैं। पालघर की घटना से पूरा देश स्तब्ध था, सोशल मीडिया पर वायरल घटना के वीडियो ने तब भी मनुष्यता पर प्रश्न खड़े किए थे। ऐसी घटनाओं को रंग देने से एक नई बहस जन्म ले लेती है। भीड़ हिंसा वह सामाजिक विकृति है, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करती। भारत जैसे राष्ट्र, जिसमें भिन्न भिन्न जाति, धर्म भाषा वाले नागरिक निवास करते हैं, ऐसी घटनाएं उसकी प्रकृति के प्रतिकल सिद्ध होती हैं। प्रश्न मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर भी उठते हैं कि हम हिंसा के प्रति इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? किसी अफवाह मात्र के आधार पर अपना विवेक शून्य कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर हम साबित क्या करना चाहते हैं।

ऐसी घटनाओं पर क़ानूनी रूप से अंकुश लगाने के लिए सबसे पहला प्रयास मणिपुर ने लिचिंग निरोधक कानून बना कर किया था। उसके बाद राजस्थान और फिर पश्चिम बंगाल की सरकारें भी भीड़ हिंसा की घटनाओं को गंभीर मानते हुए इनकी रोकथाम हेतु क़ानून पारित कर चुकी है। पश्चिम बंगाल (भीड़ हिंसा रोकथाम) विधेयक, 2019 में किसी व्यक्ति को घायल करने वालों को तीन वर्ष से आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और अगर उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। वहीं राजस्थान में भीड़ हिंसा पर आजीवन कारावास तथा पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, पर ऐसा कर देने से भीड़ हिंसा की घटनाओं में कमी आई है क्या?

भीड़ हिंसा कितनी गंभीर समस्या है, इस बात का आंकलन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त चिंता के आधार पर किया जा सकता है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने लिचिंग पर अंकुश लगाने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा भीड़ हिंसा की जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही विशेष कार्यबल, जो ऐसे लोगों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करें, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं या अफवाह फैला रहे हैं, का गठन करने को कहा था। ये सब बातें सुनने में बेहद अच्छी लगत है, पर धरातल की वास्तविकता इसके उलट होती है। न्यायालय ने उस समय टिप्पणी की थी कि 'कोई भी नागरिक अपने आप में क़ानून नहीं बन सकता है। लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाज़त नहीं दी जा सकती।' इससे ज़ाहिर होता है कि भीड़ किस प्रकार क़ानून से ऊपर होती जा रही है।

वैश्विक संदर्भ में बात की जाए तो 'लिचिंग' शब्द अमेरिका से आया हैं अमेरिकी क्रांति के दौरान वर्जीनिया के बेडफर्ड काउंटी के चार्ल्स लिंच अपनी निजी अदालतें बैठाने लगे और अपराधियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सज़ा देने लगे। वहां लोगों को भीड़ के सामने पेड़ों या पुतलों पर लटका कर अंग-भंग कर और ज़िंदा जला कर अमानवीय तरीके से हत्या की जाती थी। अमेरिका स्थित 'नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट आफ कलर्ड पीपुल के आंकड़ों के अनुसार 1882 से 1968 तक अमेरिका में 4,743 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा की गई। लिचिंग के शिकार लोगों में जहां 3,466 अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी थे, वहीं इनमें 12,97 श्वेत लोग भी थे।

वैश्विक संदर्भ में बात की जाए तो 'लिचिंग' शब्द अमेरिका से आया हैं अमेरिकी क्रांति के दौरान वर्जीनिया के बेडफर्ड काउंटी के चार्ल्स लिंच अपनी निजी अदालतें बैठाने लगे और अपराधियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सज़ा देने लगे। वहां लोगों को भीड़ के सामने पेड़ों या पुतलों पर लटका कर अंग-भंग कर और ज़िंदा जला कर अमानवीय तरीके से हत्या की जाती थी। अमेरिका स्थित 'नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट आफ कलर्ड पीपुल के आंकड़ों के अनुसार 1882 से 1968 तक अमेरिका में 4,743 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा की गई। लिचिंग के शिकार लोगों में जहां 3,466 अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी थे, वहीं इनमें 12,97 श्वेत लोग भी थे।

हमारे देश में भीड़ यानि मॉब लिचिंग की प्रवृत्ति हर काल में देखी गई है। भीड़ ने सबसे पहले डायन बता कर महिलाओं को अपना शिकार बनाया, फिर यह प्रवृत्ति बदली और गोहत्या की अफवाहों पर भीड़ गोरक्षक बन कर मैदान में कूद पड़ी। कुछ समय बाद बच्चा चोरी के शक में भीड़ द्वारा पीटने का तीसरा चलन सामने आ गया।

05 अप्रैल, 2017 को राजस्थान के अलवर में दो सौ लोगों की गोरक्षक भीड़ ने दूध का व्यापार करने वाले पहलू ख़ान को मार दिया। इस मामले को सर्वाधिक सुर्ख़ियां मिलीं, पर इस घटना को सर्वाधिक रंग दे दिया गया। इंडिया स्पेंड वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2010 से 2017 के बीच दर्ज तिरसठ मामलों में से सत्तानबे प्रतिशत मामले पिछले तीन सालों के दौरान दर्ज हुए। रिपोर्ट की मानें तो वर्ष 2022 से अब तक सामुदायिक घृणा से प्रेरित ऐसी एक सौ अटठाईस घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें सैंतालीस लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं, जिनमें सैंतालीस लोगों की मृत्यु हुई और एक सौ पचहत्तर लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जनवरी, 2017 से 05 जुलाई, 2018 के दरम्यान दर्ज 69 मामलों में केवल बच्चा चोरी की अफवाह के चलते 33 लोग भीड़ हिंसा में मारे जा चुके हैं और 99 लोग

बाक़ी पेज 11 पर

अफ़ग़ानिस्तान : अंतरिम सरकार में नए मंत्री, उपमंत्रियों के नामों की घोषणा

तालिबान ने अफग़ानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार में कई और मंत्रियों और उपमंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है लेकिन दुनिया भर के दबाव के बावजूद तालिबान सरकार के इस विस्तार में किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। एक प्रेस कांफ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कैबिनेट विस्तार की जानकारी देने के दौरान कहा कि सरकार में बाद में कभी महिलाओं को शामिल किया जा सकता है हालांकि उन्होंने इसका कोई ख़ास समय नहीं बताया।

आइएएनएस के अनुसार मुजाहिद ने कहा कि शीर्ष तालिबान नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश पर बड़े व्यापारी हाजी नूरूद्दीन अज़ीज़ी को कार्यवाहक वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं कलंदर एबाद को कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वालों को उप मंत्री बनाया गया है। मुजाहिद ने कहा कि इस कैबिनेट विस्तार में अल्पसंख्यकों, जैसे हाजरा समुदाय का ध्यान रखा गया है। तालिबान ने हाल के दिनों में शीर्ष पदों पर बड़े नेताओं के नाम घोषित कर अपनी सरकार का प्रारंभिक खाक़ा पेश करने के बाद अब विस्तार किया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कह रखा है कि वह तालिबान की कथनी और करनी को देखेगा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले व्यवहार को देख-परख कर नई अफग़ान सरकार को मान्यता देने पर विचार करेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि शरीयत के अनुसार अफग़ान किशोरियों के पढ़ने लिखने और नौकरी करने के लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यह नियम कब तक तैयार होंगे इसकी भी कोई समय सीमा नहीं बताई। सरकार को मान्यता देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की झिजक पर टिप्पणी करते हुए मुजाहिद ने कहा कि इस काम को लटकाए रखने का कोई कारण नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों की ज़िम्मेदारी है कि वह हमारी सरकार को मान्यता दें। इसके साथ ही एशियाई, यूरोपीय और इस्लामिक देशों की ज़िम्मेदारी है कि वे हमारे

बाक़ी पेज 11 पर

तालिबान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना

अफग़ानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान का तालिबान ने करारा जवाब दिया है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी भी देश को उससे समावेशी सरकार गठित करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है।

तालिबान के प्रवक्ता और उप सूचना मंत्री जबीउल्ला मुजाहिद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान समेत कई देशों ने अफग़ानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन की ज़रूरत बताई है। अफग़ान सरकार को लेकर इमरान ख़ान के हालिया बयान के बारे में पूछे जाने पर मुजाहिद ने डेली टाइम्स से कहा कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश को इस्लामिक अमीरात से अफग़ानिस्तान में समावेशी सरकार गठित करने के लिए कहने का हक़ नही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इमरान ख़ान ने कहा था कि अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए अफग़ानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने को लेकर तालिबान के साथ पाकिस्तान ने बातचीत शुरू की है। इससे पहले तालिबान नेता मुहम्मद मोबिन ने भी इमरान खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था, 'क्या समावेशी सरकार का मतलब यह है कि उसमें पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों और जासूसों को जगह मिले।'

तालिबान ने उज्बेक को आधिकारिक भाषा से हटा दिया है। तालिबान की ओर से अफग़ानिस्तान को लेकर अंतरिम कानून जारी किया गया है। इसमें नई व्यवस्था स्थापित करते हुए आधिकारिक भाषा के रूप में सिर्फ पश्तो और दरी को ही रखा गया है। पहले उज्बेक भी आधिकारिक भाषा थी। अफगानिस्तान में शिक्षिकाओं को भविष्य की चिंता सताने लगी है। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने सातवीं से 12वीं तक के शिक्षकों और छात्रों को स्कूल में आने के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें शिक्षिकाओं और छात्राओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कई शिक्षिकाओं ने कहा कि अपने परिवार में वे ही अकेली कमाने वाली सदस्य है।

एम्स : स्मार्ट लैब में एक सैंपल से दर्जनों जांच, 24 घंटे के अंदर मिल रही रिपोर्ट

आधुनिक तकनीक से लैस एम्स की स्मार्ट लैब मरीज़ों के लिए सुकून लेकर आई है सिर्फ एक सैंपल में दर्जनों जांच संभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर मरीज़ को रिपोर्ट पहुंच रही है। यही नहीं, अगर किसी मरीज़ की रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर को संदेह है, तो एक बटन दबाने पर पुराने सैंपल से फिर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। जिस एम्स में ब्लड और यूरिन से जुड़ी जांच के लिए कई-कई दिन का इंतज़ार करना पड़ता था, अब वे ऐसी सभी जांचें एक दिन में हो रही हैं।

एम्स के स्मार्ट लैब के प्रमुख डॉ. सुब्रत सिन्हा ने बताया कि पहले की तुलना में यह लैब पूरी तरह से ऑटेमेटिक और मैन्युअल फ्री है। इसमें अधिकांश काम ऑटोमैटिक है। यही वह है कि कम समय में ज़्यादा जांच की जा रही है। पूरी लैब मॉडर्न मशीन से लैस है। पिछले हम रोज़ाना 1000 से 1200 सैंपल का ही टेस्ट तक पाते थे, अभी 3200 से ज़्यादा सैंपल की जांच कर पा रहे हैं। अब हम इसे बढ़ाकर 20 प्रकार के अलग अलग टेस्ट करने होते हैं।

स्मार्ट लैब के इंचार्ज डॉ. सुदीप दत्ता ने कहा कि इस लैब की विशेष बात यह है कि अभी 85 तरह के टेस्ट कर रहा है, आने वाले समय में यह 270 तरह के टेस्ट करने में सक्षम हो जाएगी। जिस तरह की क्षमता है उसके अनुसार 02 लाख टेस्ट कर सकते हैं। जब यह पूरी क्षमता से काम करेगी तो औसतन हर माह 05 लाख मरीज़ों को इसका फायदा होगा। यही नहीं, मरीज़ को पहले अलग-अलग जगहों पर सैंपल देना होता था, इस स्मार्ट लैब के शुरू होने से कम से कम उनका डेढ़ किलोमीटर चलना कम हो गया।

डॉक्टर सुब्रत ने कहा कि पहले मरीज़ को अलग-अलग जांच के लिए अलग-अलग लैब में जाना होता था, कई बार सैंपल देना पड़ा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। एक बार सैंपल लिया तो उसी से सभी टैस्ट हो जाते हैं। इसमें जहां पर मरीज़ का सैंपल कलेक्शन होता है, वहीं पर एक बारकोड दिया जाता है, उस बारकोड में मरीज़ की कौन कौन सी जांच होनी है, इसके बारे में लिखा होता है। हर मशीन की अपनी-अपनी क्षमता है। अगर कोई मशीन 20 तरह का टैस्ट कर सकती है, लेकिन जब कोई सैंपल उस मशीन से गुज़रता है तो बारकोड में जितने टेस्ट लिखे होते हैं, तो उतने के लिए सैंपल वह मशीन ले लेती है और सैंपल से भरे जार को दूसरी मशीन पर भेज देती है। इसी तरह बाकी मशीन भी काम करती है। डॉक्टर श्याम प्रकाश ने कहा कि हर मशीन एक दूसरे से कनेक्ट है। पहली मशीन सैंपल के जार का ढक्कन हटाती है और उसे आगे बढ़ाती है। यह सब ऑटोमैटिक होता है। फिर एक ट्रैक बना हुआ है, मशीन अपने बारकोड के अनुसार जार के सैंपल लेती है और उसे आगे भेज देती है। बारकोड के अनुसार सभी टैस्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार हो जाती है और वह सेंट्रल सर्वर के ज़रिए अपलोड हो जाती हैं मरीज़ की रिपोर्ट शाम तक तैयार हो जाती है और उन्हें दूसरे दिन इलाज से पहले मिल जाती है। इस लैब की विशेषता बताते हुए डॉक्टर तुषार सहगल ने कहा कि स्मार्ट लैब के बाद ग़लती की संभावना कम हो गई है। एक सैंपल से सारी जांच की जा रही है। अगर किसी जांच रिपोर्ट पर डॉक्टर को संदेह है या डॉक्टर फिर से जांच कराना चाहते हैं, तो उसी सैंपल से जांच की जा सकती है। सैंपल तीन दिनों के लिए प्रिजर्व रखा जाता है, एक बटन दबाते ही सैंपल फिर से जांच के लिए अपने आप ट्रैक पर आ जाता है और जांच की जाती है। लेकिन तीन दिन के बाद सैंपल अपने आप डिस्पोज हो जाता है, इसके बाद मरीज को फिर से नया सैंपल देना पड़ता है। कुल मिलाकर एम्स की यह स्मार्ट लैब मरीज़ों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ❑❑

दिल्ली स्थिति झीलों के विकास के लिए कमर कसी दिल्ली सरकार ने

दिल्ली के चहूंमुखी विकास के लिए केजरीवाल सरकार कटिबद्ध है। हाल में उन्होंने 'मेरी दिल्ली देखो' नामक ऐप जारी किया है जिससे दिल्ली स्थिति पर्यटन के तमाम जानकारी मिली पाएगी। इससे दिल्ली में घूमने आने वाले सैलानियों को काफी मदद मिलेगी। दूसरी ओर सरकार ने सभी झीलों को विकसित कर पर्यटन स्थलों में तब्दील करेगी। इस संबंध में पिछले दिनों तमाम जलाशयों के पुनर्विकास से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। सरकार सस्टेनेबेल मॉडल का उपयोग करके झीलों का कायाकल्प कर रही है। झीलों के आसपास पर्यावरण तंत्र को जीवंत करने के लिए देशी पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी 22 झीलों और 200 जल निकायों के पुनर्निमाण का काम पूरा करने के लिए अधिकारियों को दो वर्ष का समय दिया गया है। कीचड़ और सूखा कूड़े को साफ किया जाना चाहिए। झीलों के उचित निर्माण के साथ उनको लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार सभी झीलों को सुंदर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेषज्ञ की मदद ली जाएगी। जैन ने कहा कि तिमारपुर ऑक्सीडेशन झील और रोहिणी झील का कायाकल्प हमारी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से हैं।

संपादकीय
शांति मिशन

चीफ जस्टिस रमन्ना की चेतावनी

भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। यहां पर प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। इस लोकतंत्र की जड़ें चार स्तंभों पर खड़ी है : न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और स्वतंत्र मीडिया। कानून को ठीक करने और उसे सही प्रकार से उल्लेखित कर लागू करने के लिए न्यायपालिका है, प्रशासन से कोई चूक होती है तो उसे सही राह दिखाने के लिए विधायिका का दरवाज़ा खुला हुआ है। प्रत्येक स्तंभ का अपना महत्व है और अगर इनमें से कोई भी अपने जगह से हिलते नज़र आने आते हैं तो स्वतंत्र मीडिया की ज़िम्मेदारी आती है कि वह प्रशासन और जनता तक यह बात पहुंचा दे कि अब देश में लोकतंत्र ख़तरे में है और देश का सत्तारूढ़ प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी सही प्रकार से नहीं अदा कर पा रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या वाक़ई यह हमारे लोकततंत्र के चार स्तंभ अपना कर्तव्य पूर तरह निभा रहे हैं? या उनके किसी काम से लोकतंत्र की आत्मा को आघात पहुंच रहा है?

अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.वी. रमन्ना ने अपनी दो मीटिंगों में पुलिस और लोकसभा के बारे में जिन विचारों का इज़हार किया है उनसे तो मालूम होता है कि हमारी कार्यपालिका और विधायिका का हालचाल बहुत दुरुस्त नहीं है। यह सब को मालूम है कि पुलिस और जनता के रिश्ते जो दोस्ताना होने चाहिए वह अधिकतर ज़ालिम और मज़लूम का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें एक आम व्यक्ति ही शिकार होता है। वह जहां तक एक ओर पुलिस उत्पीड़न का शिकार होता है वहीं क़ानून की चक्की में भी वही पीसता है, पुलिस स्टेशन एक तरह से प्रताड़ना गृह बन चुके हैं। जहां क़दम-क़दम पर मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। गंभीर बात यह है कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों तक को निशाना बना दिया जाता है जो उनके लिए अधिक तौहीन और अपमान की बात होती है और इस सूरतेहाल से देश का कोई राज्य, ज़िला बल्कि पुलिस स्टेशन तक बचा नहीं रह पाया है। अभी पिछले दिनों जनता के इस दुख को महसूस करते हुए माननीय न्यायाध ीश महोदय श्री रमन्ना ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के विजन और मिशन ऐप और डाक्यूमेंट की शुरुआत करते हुए कहा कि मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन पुलिस स्टेशनों में ही होता है। हमारे यहां आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए क़ानून है। इसके बाद भी हिरासत में उत्पीड़न और मौत के मामले सामने आते रहते हैं। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस थाने में तुरंत कानूनी मदद नहीं मिल पाती। इसी कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश श्री रमन्ना ने यह भी कहा कि कई रिपोर्टों से पता चलता है कि विशेष अधिकार प्राप्त लोगों पर भी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की ज़्यादातियों को रोकने के लिए लोगों को संवैधानिक अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताना ज़रूरी है। श्री रमन्ना ने जो ऐप जारी किया उसके द्वारा लोगों को मुफ्त क़ानूनी सहायता दी जा सकेगी ऐसा उन्होंने कहा। जो पीड़ा हिन्दुस्तान के हर आम और विशेष नागरिक को है उसी को श्री रमन्ना ने अभिव्यक्त किया। उनका यह कहना है कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां क़ानून का शासन बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज के उच्च वर्ग और ग़रीब वर्ग के लिए न्याय के अवसर एक समान हों। यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग होने के कारण किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। एक विशेष महत्व की बात कहते हुए जस्टिस रमन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अतीत से कभी भविष्य तय नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे भविष्य का स्वप्न देखना चाहिए जहां समानता हो और सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए ''न्याय तक पहुंच'' नाम से मिशन चलाया जा रहा है, जो सतत् चलेगा।

जहाँ तक विधायिका और संसद का संबंध है माननीय न्यायाधीश ने एक अन्य अवसर पर यह भी कहा था कि हमारी संसद के क़ानूनों में स्पष्टता नहीं रही। हम नहीं जानते कि ये कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह जनता के लिए हानिकारक हैं या लाभदायक। उन्होंने कहा कि आज संसद में कार्यवाही के दौरान उचित बहस या चर्चा नहीं होती। जस्टिस रमन्ना ने संसद की तुलना पहले के समय की संसद से की है, जब संसद वकीलों से भरा हुआ रहता था। स्पष्टत: उनका संकेत राज्यसभा में राजनीतिक सौदेबाज़ी के लिए उन लोगों को सदस्यता देने की ओर है जो देश के बुद्धिजीवी नहीं, अपितु सत्ताजीवी लोग हैं और लोकसभा में भी बहुत से ऐसे बाहुबली पहुंच जाते हैं जिनको क़ानून और संविधान की जानकारी नहीं होती। केवल धन बल बाहुबल से वोट लेकर वे सांसद बन जाते हैं, पर न क़ानून की व्याख्या कभी कर पाते और समझते हैं, न ही जनता को उचित प्रतिनिधित्व दे पाते हैं।

संसद में संख्या बल बढ़ाने के लिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां, उसकी चुनाव जीतने की क्षमता के कारण टिकट दे देती हैं। ऐसे व्यक्तियों का धन-बल भी चुनावी टिकट पाने में बहुत सहायता करता है। वैसे भी आज सभी राजनीतिक पार्टियां संसद में ऐसे लोगों को चाहती हैं जो उनके संकेत पर समर्थन या विरोध में हाथ खड़ा कर दें। कौन सा क़ानून क्यों पास क्यों पास किया जाता है इसकी जानकारी उन्हें हो या न हो। ऐसे लोग ही सत्तपति राजनीतिक दलों को मनमानी करने में सहायक होते हैं और निस्संदेह वे भी सांसद बनकर जनहित नहीं, अपितु अपना हित करने में, मनमानी करने में स्वतंत्र हो जाते हैं। जस्टिस रमन्ना ने हिन्दुस्तान के आम आदमी का दर्द महसूस करते हुए अपने विचार व्यक्त मशहूर कानूनविद्, न्यायाधीश वी.डी. देसाई 'स्मृति ट्रस्ट' द्वारा आयोजित कानून का शासन के विषय पर यह विचार व्यक्त किए। अपने इन विचारों के द्वारा उन्होंने जनता के घायल दिलों की समय रहते व्याख्या कर दी। देश की जनता जहां क़दम-क़दम पर पुलिस के ज़ुल्म की शिकार है वहीं वह संसद में नेताओं को देखकर मायूस हुए बिना नहीं रह पाते। अब प्रश्न यह है कि आखिर इसका इलाज क्या है और वह कौन सी संस्था है जो इन कर्मियों/ख़ामियों को दूर करके लोकतंत्र की सुरक्षा का दायित्व निभा सकता है।

हमारे विचार में अब समय आ गया है कि हमारी न्यायपालिका इन दोनों अहम संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर नज़र रखने के लिए अपनी निगरानी में कोई ऐसी संस्था स्थापित करे जो समय-समय पर हालात के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करती रहे, इस अवसर पर हम श्री रमन्ना से यह अपील करना चाहते हैं कि वह तमाम राज्यों और केन्द्रीय सरकारों से यह मालूमात हासिल करें। पिछले 25 सालों में पुलस हिरासत में कितने लोगों की मौत हुई और जेलों में बंदी के दौरान कितने लोग मारे गए और इन लोगों क संख्या क्या है जो एक लम्बे समय से बिना किसी सज़ा के ऐलान के जेलों में बंद हैं और वह उस सज़ा से कहीं अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं जो उन्हें इस अपराध पर दी जाती, जिसके तहत पकड़े गए थे इस अवसर पर हम अपने माननीय मुख्य न्यायाधीश से एक और विनती करना चाहते हैं कि उन्होंने बार-बार कहा कि न्याय हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है वह सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी कोई क़दम उठाए। सबको मालूम है कि भारत में कुछ व्यक्ति हैं जो न्याय प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकते हैं वर्ना अधिक संख्या तो उन लोगों की है जो निचली अदालत तक पहुंचने के ख़र्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते।

बहरहाल हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जनता के दुखों को महसूस करते हुए जो कुछ भी कहा है उसका हमें स्वागत करना चाहिए और अंत में हम एक बार उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिस सच्चाई के साथ बीमारी को समझा है उसी हौंसले के साथ उसकी दवा भी बता दें। हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके प्रभाव दूर तक पहुंचेंगे और उसके परिणाम भी दूर तक पहुंचने वाले होंगे। ❑❑

तारीख़े इस्लाम
ख़ुतबाते सीरते तैयिबा
मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी — क़िस्त-92

ग़ज़्वा-ए-मौता

सन 8 हि. में एक अहम वाक़िआ यह पेश आया कि पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत हारिस बिन उ़मैर अज़्दी रज़ि अल्लाहु अ़न्हु को बुसरा के हाकिम शुरहबील ग़स्सानी के नाम एक तहरीर लेकर भेजा, उस ने यह हरकत की कि पैग़म्बर का जो ख़त लेकर सहाबी हारिस बिन उ़मैर गए थे उनको क़त्ल कर दिया, हालांकि तमाम क़ौमों में सफ़ीरों का क़त्ल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, तो पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को बड़ा सदमा हुआ, और आप ने उन से बदला लेने के लिए 3000 के क़रीब सहाबा का एक लश्कर तरतीब दिया।

आप ने फ़रमाया कि सिपह सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ि अल्लाहु अ़न्हु रहेंगे, और फ़रमाया कि अगर वह शहीद हो जायें तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ि अल्लाहु अ़न्हु झंडा उठायेंगे, और अगर वह भी शहीद हो जायें तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि अल्लाहु अ़न्हु, फिर फ़रमाया कि अगर वह भी शहीद हो जायें, तो जिसको चाहो अपना अमीर बना लेना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस फ़रमान से सहाबा ने समझ लिया कि इन तीनों का शहीद होना तो यक़ीनी है, चुनान्चे यह लश्कर रवाना हुआ, जब क़रीब पहुंचे, तो एक अजीब व ग़रीब सूरते हाल सामने आई, वह यह कि उस शुरहबील नामी सरदार ने इलाक़े की एक लाख फ़ौज मुक़ाबले के लिए भेजी, और उस की मदद के लिए ''हिरक़ल'' ने मज़ीद एक लाख फ़ौज भेजी थी, गोया कि उस तीन हज़ार की फ़ौज को दो लाख फ़ौज से मुक़ाबला करना है, जो बड़ा अहम मसअला था।

चुनान्चे मशवरा हुआ कि क्या करना चाहिये? हुज़ूर को ख़बर दी जाए, वापस चले जायें या आगे बढ़ें? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि अल्लाहु अ़न्हु बड़े शायर और जज़्बाती आदमी थे, यह खड़े हुए और फ़रमाया कि देर किस बात की है? मुसलमान तो हर हाल में जीता हुआ है, अगर शहीद हो जायें तो शहादत से बढ़ कर क्या सआ़दत है? और अगर कामियाब हो गए तो कामियाबी है ही, पीछे हटने का क्या सवाल है? तो लोगों में जोश पैदा हो गया और यह तीन हज़ार का लश्कर दो लाख की फ़ौज से टकराया, ज़ैद बिन हारिसा रज़ि अल्लाहु अ़न्हु शहीद हुए, जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने झंडा उठाया, एक हाथ कट गया, तो बायें हाथ में झंडा पकड़ा, बायाँ हाथ कट गया, तो दोनों मोंढे मिला कर झंडा पकड़ा, तो एक मलऊ़न काफ़िर ने ऐसी तलवार मारी कि बदन के दो टुकड़े हो गए, तो अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने झंडा उठाया, और अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि अल्लाहु अ़न्हु भी लड़ते लड़ते शहीद हुए, तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने झंडा उठाया, और ऐसी बहादुरी से लड़े, फ़रमाते हैं कि 9 तलवारें मेरे हाथ में टूटी हैं, और तदबीर यह इख़्तियार की कि ये तीन हज़ार का लश्कर पीछे हट गया और दुश्मन आगे बढ़ा तो घेर लिया और जितना नुक़सान पहुंचाना था पहुंचाया, और अपने सिर्फ़ बारह आदमी शहीद हुए, और बक़ि"या सब को बहिफ़ाज़त बचा कर मदीना ले आए। (अल बिदाया वन्निहाया, 4/632, ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 664)

आप अंदाज़ा लगाइये कि इतनी बड़ी फ़ौज से जंग हो और कई दिन जारी रहे और कुल बारा आदमी शहीद हुए, उन के कितने मारे गए? इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिये कि 9 तलवारें उन्होंने तोड़ डालीं, यह सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मदद और नुसरत है, लेकिन पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को इन तीनों सहाबा की शहादत का बड़ा सदमा था। (जारी)

पकड़ लो बादल, मजीठिया को, कौन रोक रहा है, सरकारी तुम्हारी है

कैप्टन अमरेन्द्र

पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से कैप्टन अमरेंद्र सिंह सुर्खियों में छाए हुए हैं। सी. एम. पद चाहे छिन गया है मगर वह अभी भी शाही अंदाज़ में सूबे की राजनीति में अपनी अहमियत बनाए हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के प्रति तो उनके तेवर कड़े हैं ही, सत्ता के छः माह रहते उन्हे बरतरफ करने में अहम भूमिका निभाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को वह किसी सूरत में बख़्शने के मूड में नहीं हैं। उनके इस आक्रामक रुख़ को देखते हुए जहां कांग्रेस में खलबली मची है वहीं विरोध ी दल खुश हैं। कैप्टन के प्रति पार्टी नेताओं के विरोध मुख्यमंत्री पद जाने के बाद बने हालात और उनकी भविष्य की राजनीति पर उनसे बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

सवालः- आपकी पार्टी के कई नेता आरोप लगा रहे थे कि आपने ड्रग केस में मजीठिया और बेअदबी मामले में बादलों पर कोई कार्रवाई नहीं की?

जवाबः- वो चाहते हैं कि मैं मजीठिया को अंदर करूं, मैं कैसे कर दूं या बहबलकलां, कोटकपुरा, बरगाडी पर बादलों को अंदर कर दूं मगर कानून नाम की कोई चीज़ भी है, मैं कानून के मुताबिक काम कर रहा था। खैर, हुण ओनां दी सरकार है। फड़ लो बादल नूं, फड़ लो मजीठे नूं, कौन रोक रिहा, तुहाडी सरकार बनगी है। (अब तो उनकी सरकार है, उन्हें कौन रोक रहा है। जाओ और बादलों व मजीठिया को कर दो अंदर) जब अमृतसर में पूछा था चन्नी से कि बादलों का अब क्या करोगे तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे भाई हैं, पकड़ लो भाई को जाकर। बहबलकलां, कोटकपुरा, बरगाड़ी जवाहरके में चार अलग-अलग एसआईटी काम कर रही हैं। 19 लोग गिरफ्तार किए, जो अब ज़मानत पर बाहर हैं। ड्रग्स की तस्करी में 66000 अरैस्ट किए 42000 अभी भी जेल में हैं। 055 किंगपिन विदेश से पकड़ कर लाए। उन्हें हम केन्द्र की मदद के बिना तो नहीं ला सकते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं केन्द्र से जाकर मिलता था लेकिन केन्द्र की मदद के बिना कौन-सा राज्य काम कर सकता है।

सवालः- सुखजिंदर रंधावा का कहना है कि जैसे प्रताप बाजवा को हटाकर आपको प्रधान बनाया गया था तो अब यदि बदलाव की मांग उठी थी तो दिक्क़त नहीं होनी चाहिए थी?

जवाबः- अच्छा, तो क्यों लड़ा था सिद्ध से। रंधावा होम मिनिस्टर बनना चाहता था लेकिन सिद्धू कहता कि वह उसे गृह विभाग नहीं लेने देगा। सिद्धू कौन है, यह फैसला करने वाला। यदि रंधावा चाहता है तो बतौर सी.एम. यह चन्नी को फैसला करना है कि किसे कौन सा विभाग देना है।

सवालः- आपने कहा था कि सी.एम. पद पर सिद्धू स्वीकार नहीं, आलाकमान ने आपकी बात मानी जो चन्नी को ले आए?

जवाबः- मैं यह नहीं कहूंगा मगर चन्नी बढ़िया इंसान है। वह सिद्धू से 100 गुणा बेहतर है। पिछले साढ़े चार वर्ष में मैंने एक मंत्री ड्राप किया अपनी केबिनेट से और वह सिद्धू था। कारण, वह अयोग्य मंत्री साबित हुआ। उसके स्थानीय निकाय विभाग में 07 माह तक फाइलें पड़ी रही बिना निपटे। जबकि वह हमारे लिए बहुत अहम विभाग था, शहरों का विकास उसके तहत आता है, इसलिए मुझे सिद्धू को निकाल कर ब्रह्म मोहिंद्रा को यह विभाग देना पड़ा। बाकी मंत्री क्यों सही चले और अकेला सिद्धू क्यों नहीं, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। अब वह एक विभाग तो चला नहीं पाया, पूरा पंजाब कैसे चलाएगा? वह तो बोलता बढ़िया है, लोग इकटठे कर लेता है, कुछ क्रिकेट का स्टांस दिखा देगा जैसे जोकर करते हैं। भीड़ जुटा लेगा मगर सिद्धू वोट नहीं डलवा सकता। हम चुनाव में फिल्म स्टार बुलाते हैं सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए, क्या लगता है उनके कहने पर कोई वोट डालता है।

सवालः- आपने सिद्धू को अपने सिसवां फार्म पर चाय पर बुलाया था, तब भी बात क्यों नहीं बनी.?

जवाबः- मैंने कहा कि हमें पार्टी के हित में मिलकर चलना चाहिए। यदि सरकार में आना चाहते हो तो आ सकते हो मगर वह पुराना विभाग नहीं मिलेगा। उसने दो सप्ताह का समय मांगा कि सोच कर बताऊंगा। लेकिन वह वापस नहीं आया, उल्टे प्रियंका गांधी को मिलने गया और उनसे कहा कि कैबिनेट में वापस नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह मेरे और मेरी सरकार के ख़िलाफ रोजाना टवीट कर रहा था। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से तब कहा भी था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो उसे रखो या मुझे।

सवालः- कांग्रेस का 2022 के चुनाव के लिए राहुल ने बढ़िया कदम उठाया है, ऐसा जाखड़ ने भी टवीट किया था?

जवाबः- जाखड़ बहुत बढ़िया इंसान हैं। मुझे उनसे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल सकता। उन्होंने कभी सरकार में दख़ल नहीं दिया और हमारा बढ़िया तालमेल पार्टी व सरकार में रहा। जो वह चाहते थे मैंने हर वो काम किया और उन्होंने भी मुझे कभी किसी काम से मना नहीं किया। इनकी तरह नहीं जैसे सिद्धू चन्नी को कुछ नहीं समझा। कांग्रेस इस तरह की नहीं थी। बीते 52 साल में मैंने इतनी सरकारें देखी लेकिन ऐसा काम नहीं देखा।

सवालः- आपने इस्तीफ़ा देने के बाद कहा था कि भविष्य के बारे में जल्द ही अपने दोस्तों शुभचिंतकों से मिलकर फैसला करेंगे। क्या फैसला किया है?

जवाबः- 52 वर्ष से राजनीति में हूं, इतने लोगों से जुड़ा हूं, इस अरसे दौरान तो इतनी जल्दी कैसे फैसला ले लूं। अभी तो किसी से मिला भी नहीं हूं। अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ कर दूंगा।

सवालः- आप कांग्रेस में रहोगे, नई पार्टी बनाएंगे या भाजपा में जाएंगे?

जवाबः- यदि कांग्रेस ने सिद्धू को चुनाव में अपना चेहरा बनाया तो उसका विरोध करूंगा। इससे बात साफ हो जानी चाहिए। कैसे करूंगा, यह आपको समय आने पर आपको बताएंगे।

सवालः- चन्नी की ताजपोशी पर हरीश रावत ने कहा था कि 2022 का चेहरा सिद्धू होंगे?

जवाबः- अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, चन्नी चेहरा होंगे और उसके बाद कहा कि चन्नी और सिद्धू, दोनों चेहरा होंगे। यह कन्फ्यूजन क्यों है। लोग एक आदमी के नाम पर वोट डालते हैं और मेरा मानना है कि चन्नी नवजोत सिद्धू से बेहतर है।

सवालः- हाल ही में चन्नी और सिद्धू द्वारा दिल्ली जाने के लिए प्राइवेट प्लेन की सेवाएं लेना चर्चा में है, इस बारे में क्या कहेंगे..?

जवाबः- क्या ज़रूरत थी, मैंने तो साढ़े 4 वर्ष में कभी जैट नहीं मंगाया। 16 सीटर जैट चार लोगों के लिए ले जाने की क्या तुक थी जब आपके पास 5 सीटर हेलिकॉप्टर है इसका कम से कम करोड़ रुपये ख़र्च आया होगा।

सवालः- हाल ही में अशोक गहलौत ने बयान दिया था कि कैप्टन पुराने सिपाही हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई क़दम नहीं उठाएंगे?

जवाबः- गहलौत मेरे पुराने मित्र हैं। मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि वह अपना राजस्थान देखें और मुझे अपना पंजाब देखने दें। ❑❑

अगर कैप्टन साढ़े चार साल फेल रहे तो दोषी अकेले वह नहीं : सरदार बलविंदर

राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना कर सभी दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सबसे ज़्यादा असर शिअद/बसपा गठबंधन पर पड़ने की बात कही जा रही है, जिन्होंने दलित फेक्टर को ध्यान में रखकर ही गठबंधन किया था। अब जब वहां दलित सीएम बन गया है तो 'दलित डेप्यूटी सीएम' का वादा कितना असर रखेगा और क्या होगी आगे की शिअद/बसपा की रणनीति, पेश है इस बारे में पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़ से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

सवालः- पंजाब में पहली बार दलित सीएम बना है, इस घटनाक्रम को आप किस नज़र से देख रहे हैं?

जवाबः- यही तो लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। पंजाब ही नहीं, जब-जब देश के किसी भी राज्य में ऐसा हुआ है, मुझे ख़ुशी हुई है आगे भी जब भी ऐसा होगा, मुझे ख़ुशी ही होगी।

सवालः- लेकिन पंजाब में तो दलित सीएम बनने से आपके सियासी समीकरण बिगड़ने का ख़तरा पैदा हो गया है?

जवाबः- मेरा कोई भी समीकरण नहीं बिगड़ने वाला। हमने पहले भी कहा था कि अकाली दल/बसपा गठबंध न सत्ता में आ रहा है और चन्नी के सीएम बनने के बाद भी हमारा यही कहना है। पंजाब चुनाव को चन्नी के सीएम बनने के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अकाली दल/बसपा की ज़मीनी ताक़त जब एक होती है तो उसके नतीजे कैसे रहते हैं, इस नज़रिए से देखना चाहिए। 1996 में अकाली/बीएसपी गठबंधन था, हम 13 में से 11 लोकसभा सीटें जीते थे।

सवालः- आप दलित डेप्यूटी सीएम के वादे के साथ चुनाव में जाएंगे, उधर कांग्रेस दलित सीएम के साथ चुनाव मैदान में होगी तो क्या दलित समाज का भावनात्मक झुकाव कांग्रेस की ओर अधिक नहीं होगा..?

जवाबः-चन्नी के सीएम बनने पर हमें कोई ऐतराज़ नही है, हमारा प्रश्न तो कांग्रेस की नीयत पर है। अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती, उसके मन में किसी दलित को सीएम बनाने की इच्छा होती तो 2017 में ही बना देती। जब चुनाव के छह माह रह गए थे और पार्टी के अंदर सीएम बनने के छह-छ दावेदार एक दूसरे का गला काटने पर आमादा थे, तो उन्हें एक बेचारा ग़रीब दलित चन्नी ही दिखा। कांग्रेस खुद कह रही है कि वह चुनाव तो सिद्धू के चेहरे पर लड़ेगी। मतलब साफ है कि उसे न तो चन्नी पर भरोसा है और न ही वह चन्नी को मज़बूत होते देखना चाहती है।

सवालः-कांग्रेस के पास यह कहने का तो मौक़ा होगा ही कि जो किसी ने नहीं किया, वह हमने कर दिया?

जवाबः- पंजाब के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के दलित सीएम से कहीं ज़्यादा हमारा दलित डेप्युटी सीएम मज़बूत होगा। उसके पास पूरी पॉवर होगी अपने समाज के लिए कुछ करने की। कांग्रेस ने दलित सीएम बना तो दिया लेकिन वह कठपुतली की तरह होगा, अपने समाज के लिए कुछ करने की पॉवर उसमें नहीं है, उसका ध्यान तो कुर्सी बचाने पर ही होगा। हमारे गठबंधन में मायावती हैं, जिन्हें पूरे देश में दलित आयकॉन माना जाता है। वह दलित हितों से कोई समझौता नहीं करती। हमारा सत्ता में आना दलित समाज के लिए कहीं ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।

सवालः- यानि यह तय है कि आप सुखबीर सिंह बादल को ही सीएम का चेहरा बना कर चुनाव के मैदान में जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला?

जवाबः- उसमें तो कोई किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं। सुखबीर सिंह बादल ही हमारे सीएम उम्मीदवार होंगे। दलित डेप्यूटी सीएम का हमारा वादा क़ायम रहेगा।

सवालः- कैप्टर अमरिंदर अकाली दल में रहे हैं। क्या कोई ऐसी गुंजाइश बनती दिख रही है कि वह 'घर वापसी' कर लें?

जवाबः- कैप्टन ने यह तो कहा है कि उनके सारे विकल्प खुले हैं। लेकिन उनके मन के भीतर क्या चल रहा है, यह तो वही बता सकते हैं। मैं उनके मन के भीतर की बात नहीं जान सकता।

सवालः- अगर वह अकाली दल के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं तो पार्टी के लिए दरवाज़ा खोलेगी या नहीं?

जवाबः- कैप्टन तो बहुत बड़े नेता हैं दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वह आना चाहेंगे तो उनको कौन रोकेगा?

सवालः- कैप्टर के पद से हटने

बाक़ी पेज 11 पर

तनावों की सियासत से बढ़े अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताज़ा आंकड़े कई मामलों में सोचने को विवश करते हैं। वर्ष 2019 की तुलना में पिछले वर्ष 28 प्रतिशत अधिक आपराधिक वारदात दर्ज की गई हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात सामाजिक अपराधों में बढ़ोत्तरी है। आंकड़े बताते हैं, 2019 के मुकाबले 2020 में सांप्रदायिक दंगों में 96 फीसदी, जातिगत हिंसा में करीब 50 फीसदी, कृषि उपद्रवों में 38 फीसदी और आंदोलन व मोर्चा के दौरान हुए फसाद में 33 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। समाज में अपराध यूं बढ़ना कानून-व्यवस्था के घटले प्रभाव का संकेत है। यह राजनीतिक दलों के लिए भी सुखद नहीं है, क्योंकि समाज के प्रश्नों को सुलझाने में पुलिस और अदालत से पहले लोग राजनेताओं से आस रखते हैं। मतलब साफ है, सियासी दलों का महत्व घट रहा है।

एनसीआरबी के आंकड़ों का एक अन्य पहलू भी है। भारत की राज-व्यवस्था के जो केन्द्र हैं, जहां देश की राजसत्ता की आत्मा बसती है, यानि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेवा प्रमुख, सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश जैसे तमाम आलिम-फाजिल रहते हैं, वहां से महज़ 200 किलोमीटर के दायरे में भी सामाजिक अपराध हो रहे हैं। यह चिराग़ तले अंधेरे जैसा है और इससे पार पाने के लिए चिराग़ को अपनी रोशनी बढ़ानी होगी। अगर राष्ट्रीय राजधानी में भी इस तरह के अपराध होते हैं, तो इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाता। विदेशी पर्यटकों से लेकर विदेशी निवेशकों तक, सभी पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है।

दरअसल, लॉकडाउन जिन तीन चीज़ों पर असरंदाज़ हुआ, वे हैं - दवाई, कमाई और पढ़ाई। इस आग में महंगाई ने घी का काम किया है। लोगों की आमदनी एक तिहाई से लेकर तीन चौथाई तक घटी है। यह स्थिति तब है, जब हम जानते हैं कि आर्थिक अपराध बेरोज़गारी और ग़रीबी से सीधे-सीधे जुड़ा है। कहा जाता है कि भूखा व्यक्ति कोई पाप ग़लत नहीं मानता, क्योंकि पेट की आग सबसे ऊपर होती है। हालांकि, कोरोना व लॉकडाउन मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण पारिवारिक हिंसा बढ़ा सकते हैं, सामाजिक हिंसा में इनका कोई हाथ नहीं होता। इसलिए दलित और सवर्णों के बीच हुई हिंसा या हिन्दू-मुसलमान विवाद अथवा महिलाओं के ख़िलाफ़ बलात्कार जैसे अपराधों को लॉकडाउन से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए क़ानून व्यवस्था से डिगता भरोसा और व्यवस्था का चरित्र कुसूरवार है।

राजनीतिक दल किस तरह से अपराध को खाद-पानी देते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। यहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर हुए थे। रसोई में पकने वाले खाने से लेकर शादी ब्याह तक में राजनीतिक दलों ने अपनी दावेदारी दिखाई थी। इसका लाभ कुछ दलों को मिला भी। नतीजतन, इसको एक लिहाज़ से राजनीतिक स्वीकृति मिल गई। यही वजह है कि यहां हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान (अब तालिबान भी) जैसी बहसें ख़ूब हो रही है। कोई यह कह सकता है कि बीमारू राज्य होने के कारण यहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना आसान है, लेकिन एनसीआरबी बताता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी, जो अपेक्षाकृत विकसित हैं, सामाजिक अपराध बढ़े हैं। वजह साफ है, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक बनावट मराठा व ग़ैर मराठा की है और इस सियासत करने वाले दल सत्ता में हैं। वहां विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनकी भी ख़ुराक़ हिन्दू मुसलमान और मराठी ग़ैर मराठी जैसे मुद्दे हैं इसलिए महाराष्ट्र और बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के संदर्भ बेशक अलग-अलग हों, लेकिन कारण एक ही हैं, सामाजिक तनावों का राजनीतिकरण। लिहाज़ा, राजनीतिक दलों में यह सहमति बननी चाहिए कि धर्म, भाषा और जाति के सवालों पर से संविधान सम्मत तौर तरीक़ों को अपनाएंगे।

कहा जाता है कि भूखा व्यक्ति कोई पाप ग़लत नहीं मानता, क्योंकि पेट की आग सबसे ऊपर होती है। हालांकि, कोरोना व लॉकडाउन मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण पारिवारिक हिंसा बढ़ा सकते हैं, सामाजिक हिंसा में इनका कोई हाथ नहीं होता। इसलिए दलित और सवर्णों के बीच हुई हिंसा या हिन्दू-मुसलमान विवाद अथवा महिलाओं के ख़िलाफ़ बलात्कार जैसे अपराधों को लॉकडाउन से नहीं जोड़ा जा सकता।

ज़ाहिर है, हमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। हमारे यहां नागरिकता निर्माण के ज़रिये ही राष्ट्र-निर्माण होगा। यूरोप में राष्ट्र निर्माण में धर्म और भाषा ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन हम बहुभाषी और बहुधर्मी देश हैं। यहां एक बार धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन चुका है, इसलिए धर्म वाले रास्ते पर जाने से और बिखराव पैदा होगा। हमें समझना होगा कि अलग होने के बावजूद पैदा होगा। हमें समझना होगा कि अलग होने के बावजूद पाकिस्तान एकजुट नहीं रह सका और धर्म के नाम पर वहां इस क़दर झगड़े बढ़े कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग होना पड़ा।

अपने यहां इसको लेकर पहले से सतर्कता रखी गई है। भाषा के प्रश्न पर हमने भाषायी राज्यों का गठन करके भाषायी असुरक्षा को घटाया है। आज तमिलनाडु में कोई द्रविड़स्तान की मांग नहीं करता। ओडिशा और बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में अब भाषा के आधार पर कोई तनाव नहीं है। जैसे हमने भाषा को सम्मान देते हुए बहुभाषी भारत को स्वीकार किया, उसी तरह बहुधर्मी भारत को स्वीकार करने के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। आजकल चारों ओर 'कॉमन कॉज' यानि सामान्य नागरिक अधिकार की वकालत खूब हो भी रही है। पुरानी पीढ़ी बेशक अपने प्रश्नों को धर्म और जाति के चश्मे से देखने की आदी हो, लेकिन नए आयु के बच्चे मानने लगे हैं कि धर्म आस्था की चीज़ है और जाति सामाजिक जीवन का आधार। आज उनकी ज़रूरत रोजी, रोटी और सुरक्षा है। इसलिए नियमों को बदलना ज़रूरी है।

इस लिहाज़ से तीन चरणों में समाधान दिख रहा है। पहला, सभी को नागरिक के रूप में क़ानून और मर्यादा के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। धर्म, भाषा, जाति और लिंग-भेद की दृष्टि से नहीं, बल्कि क़ानून व्यवस्था के संदर्भ में सभी को भारत मात्र का नागरिक मानना ज़रूरी है। दूसरा चरण, हमें नागरिकता-निर्माण की ओर ध्यान देना होगा। इसमें शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक दल और धर्म व संस्कृति के केन्द्रों का भी खासा योगदान है और तीसरा, जहां कहीं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग भेद या अमीरी गरीबी के आधार पर कोई अन्याय कर रहा हो, उससे सख़्ती और कम समय में निपटना ज़रूरी है। अगर न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था आपत्तिजनक परिस्थिति से जुड़े अपराधों को लेकर न्यूनतम समय में स्पष्ट न्याय का अभ्यास करने लगेंगे, तो लोग आपस में उलझने के बजाय पुलिस और न्यायालय पर भरोसा करेंगे।

कुल मिलाकर, क़ानून व्यवस्था को सुधारना होगा, सत्ता व्यवस्था को अपने अंदर झांकना होगा और नागरिकता के निर्माण की ओर ध्यान देना होगा, ताकि बतौर नागरिक लोग अपने कर्तव्य कर सकें और अपने अधिकारों के इस्तेमाल का भरोसा उनमें पैदा हो। ❑❑

रोज़गार .....

उज्जवल भविष्य के लिए प्लॉनिंग के साथ लगन भी ज़रूरी

अक्सर लोग थक हारकर बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यकीन मानिए हरवक्त आपके पास प्रोग्रेस का वक्त होता हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप बैठ जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत आशावादी हूं, पर बहुत उतावला भी हूं। शायद उतावलेपन ने मुझे कम उम्र में ही वह सब करवाया, जो ज़्यादातर लोग बड़ी उम्र में भी नहीं कर पाते।

सोचें मत, लग जाएं

अगर हमारी सोच सही है और हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो बस इतना ही काफी नहीं हैं आपको अपनी सोच को एक्शन में बदलना होगा। किसी चीज की धुन को कैसे अमल में लाएं, इसके लिए ज़रूरी है एक्शन लें। विचार कई लोगों के पास होते हैं। असल बात उस पर अमल करने की होती है। यह तभी होगा, जब आपको सही दिशा की पहचान होगी। सही रास्ता ही आपको सही मंज़िल तक ले जाएगा।

सही दिशा का चयन

आप सही दिशा में तभी जा सकते हैं, जब आपके साथ अच्छे लोग होंगे। आपके दोस्त हों, आपके टीचर अच्छे हों। बेहतर और साफ चरित्र वाले लोग आप से जुड़ते रहें। आसपास अच्छे रहेंगे तो आप खुद-ब-खुद आगे बढ़ते रहेंगे। गलत लोग रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना कुछ बर्बाद कर लिया।

आपके लिए कोई बना बनाया रास्ता तैयार नहीं रहेगा। आपको कुछ तो करना ही होगा। कभी लोगों को यह भी लग सकता है कि आप सनकी हैं। कई बार आपके क़दम मंज़िल के करीब हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बारे में पता ही नहीं चल पाता या आपको वह रास्ता नज़र ही नहीं आता। इसलिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। साथ ही, यह भी देखते रहना होगा कि कौन सा रास्ता आपको मंज़िल तक सबसे पहले कम से कम नुकसान में पहुंचाएगा।

आदर्शों के साथ जिएँ

जब भी दुनिया को आभास होगा कि क्या हैं, आप नज़रों में आएंगे और इन्हीं मूल्यों के कारण लोग आपकी ओर खींचते चले जाएंगे। माइक्रोसाफ्ट का ही उदाहरण लें। हमारा जज़्बा दुनिया बदलने का था। इसीलिए इससे लोग जुड़ते चले गए और हम सबकी लाइफ टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन से और भी बेहतर बनती चली गई।

इनोवेशन बहुत ज़रूरी

आप किसी भी क्षेत्र में हों, पढ़ाई, जॉब, समाज सेवा में या फिर आप हाउस वाइफ ही क्यों न हों। हर जगह आपको इनोवेशन करते रहना होगा। तभी आप खुश रह पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। एक ही तरह के ढर्रे पर चलते रहने से न तो आपको कुछ हासिल होगा और न ही आप दुनिया को कुछ दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं होता है।

हर काम की हो प्लानिंग

ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा तरीक़ा है, जिससे सारी समस्याओं का हल मिल जाए या फिर सारी टेंशन ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्हें जितना बड़ा करके देखेंगे, वे उतनी ही बड़ी होती जाएंगी। पूरा दिन काम करने के बाद मैं रात को सोने से पहले एक घंटे किताब पढ़ता हूं। यह मेरी दिनभर की टेंशन काफी कम कर देता है।

दुनिया को क्या दे सकते हैं?

अपना हर काम, हर प्रोजेक्ट पूरे प्लान के साथ करें। आपको पूरे दिन का शेडयूल बनाना चाहिए कि कब क्या करना है? कैसे करना है? कोशिश हो कि हर काम नियम समय पर ही पूरा हो। यही प्लानिंग पूरी लाइफ के साथ भी होनी चाहिए।

आप इस दुनिया से बहुत कुछ ले तो रहे हैं, लेकिन ज़रा यह भी तो सोचें कि आप वापस क्या दे रहे हैं? फिर तय करें कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं? बचपन से ही यह बात मेरे मन में बार बार हिट करती थी और आज भी हिट करती है कि मैं इस दुनिया के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। ❑❑

इस्लामी दुनिया

इस्राईल ने हमास के ठिकानों पर सैन्य विमान से किए हमले

येरुशलम : इस्राईल ने सैन्य विमान से पिछले दिनों गाज़ा पट्टी में कई लक्ष्यों पर हमले किए। यह कार्रवाई हमास नियंत्रित क्षेत्र से रॉकेट दागे जाने के जवाब में की गई। क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच लगातार तीन दिन तक संघर्ष बना रहा है। इस्राईली जेल से छह फलस्तीनी कैदियों के भागने के बाद से इस क्षेत्र में तनाव पहले ही बढ़ा हुआ था। इस बीच इस्राईल द्वारा हमास के क्षेत्र में रॉकेट दागे गए।

पाक में इमरान और शरीफ़ की पार्टी बड़े दलों के रूप में

प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की अगुआई वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ (पीटीआई) और विपक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग - (नवाज़) देश के 39 छावनी बोर्डों के लिए हुए चुनावों में दो बड़े दलों के रूप में उभरी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के मुताबिक, देश के छावनी बोर्डों के लिए मतदान हुआ था।

शरीया पर आधारित होगी तालिबान की हुकूमत में तालीम

काबुल: अफग़ानिस्तान में तालिबान शासन के बाद तालीम पर भी इस्लामी रंग चढ़ने लगा है। अब वहां शरिया कानूनों की अवहेलना करने वाले विषयों की विश्वविद्यालयों के पाठयक्रम में कोई जगह नहीं रहेगी। कार्यवाहक उच्च शिक्षामंत्री शेख़ अब्दुल बाकी हक्कानी ने कहा कि पाठयक्रम में बदलाव कर इस्लामी क़ानून के ख़िलाफ़ विषयों को हटाया जाएगा।

मलयेशिया : पीएम को विपक्ष का समर्थन

कुआलालंपुर : सत्ता में आने के एक माह के भीतर मलयेशिया के नए प्रधानमंत्री साबरी याकूब ने कई सुधारों के एवज में अपनी कमज़ोर सरकार को स्थिर करने के लिए विपक्ष का समर्थन हासिल किया। इस बीच देश की संसद का सत्र शुरू हो गया। पीएम अब अनवर इब्राहीम के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी गुट के साथ एक समझौता करेंगे जो उन्हें शासन में मज़बूती देगा।

संयुक्त राष्ट्र ने अफग़ानिस्तान के लिए मांगे 60.6 करोड़

संयुक्त राष्ट्र ने सभा करके अफग़ानिस्तान के लिए आपातकालीन फंड के तौर पर दुनिया के दानदाताओं से 60.6 करोड़ डॉलर मांगे। इस अपील के बदले सभा में करीब एक अरब डॉलर जुट गए। अमेरिका ने छह करोड़ 40 लाख डॉलर, नार्वे ने एक करोड़ 15 लाख डॉलर दान दिए। फंड में से बड़ा हिस्सा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अभियान के लिए किया जाएगा।

सामाजिक बुराईयों को दूर करने की आवश्यकता

वर्तमान काल का एक दु:खद पहलू यह है कि इस दौर में इंसान फितरत (नेचर -प्रकृति-स्वभाव) के ख़िलाफ़ बग़ावत पर उतर आया है। इंसानी ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में फितरत के ख़िलाफ़ इल्म बग़ावत बुलंद करने की वजह से आज का इंसान असंख्यक समस्याओं में घिर चुका है और वह न सिर्फ चैन-सुकून से वंचित हो चुका है बल्कि ज़िन्दगी की सुरक्षा भी मुश्किल होती नज़र आ रही है। किसी भी बस्ती में चले जाइये वहां बीमार लोगों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। सिर्फ बूढ़े या अधिक उम्र वाले लोग ही रोगों में घिरे नहीं हैं बल्कि कितने बच्चे और जवान भी ख़तरनाक प्रकार की बीमारियों में घिरे नज़र आएंगे। जबकि कुछ दशक पहले इस तरह बीमारी फैली हुई न थी और अगर कुछ शताब्दी पहले की बात करें तब तो लोग बहुत कम बीमार होते थे, आख़िर मौजूदा ज़माने और पिछले दौरों के बीच यह अंतर क्यों है इस क्त के लोग बहुत कम बीमार होते थे और आज के लोग बहुत अधिक बीमार होते हैं। क्या आज के इंसान और उस वक़्त के आदमी में अंतर है? वह शरीर के अंग जो आज के इंसानों में हैं, वह उस समय के इंसानों में न थे? दरअसल बात यह है कि उस समय के लोग असली मूल चीज़ों का प्रयोग करते थे? हालांकि उनके पास खाने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें न होती थीं। लज़ीज़ डिशें न होती थीं और रेस्त्रां भी न थे मगर उनके पास जो कुछ भी होता था वह असली फितरी और शुद्ध होता था जिसके कारण वह बीमारियों से भी सुरक्षित रहते थे और सेहतमंद भी, लेकिन आज लोगों के पास अनेक प्रकार की डिशें तो हैं मगर शुद्ध व मौलिक नहीं। सवाल यह है कि क्या यह खाने पीने की चीज़ें खुद-बुखद गैर फितरी (अशुद्ध-अमौलिक) हो गयीं? नहीं हक़ीक़त यह है कि इंसान ने खुद उन्हें फितरी बनाया है इनमें मिलावट की हैं अधिक रूपए कमाने की चाहत में ऐसे-ऐसे कैमिकल्स प्रयोग किए हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्याधिक हानिकारक हैं।

सिर्फ खाने-पीने की वस्तुएं ही ग़ैर फितरी नहीं हैं बल्कि वातावरण हवा-पानी भी प्रदूषित हो गयी हैं। इंसानी ज़िन्दगी के लिए पानी और हवा दोनों ही बहुत ज़रूरी है लेकिन आज पानी का मामला अत्याधिक पेचीदा बन चुका है। परिणाम के तौर पर लोग गन्दा पानी पीते हैं और इसके बदले में उन्हें बीमारियां मिलती हैं। अगर हवा की बात करें जो सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाख़िल होती है वह भी शुद्ध नहीं हैं क्योंकि वातावरण में प्रदूषण है इसलिए सांस के ज़रिए प्रदूषित हवा जिस्म में दाख़िल होती है और फेफड़ों, दिमाग़ और दूसरे अंगों को प्रभावित करती है। सवाल यह है कि आख़िर पानी और हवा कैसे प्रदूषित हो गए। क्यायह सब कुछ खुद-ब-खुद हुआ? हरगिज़ नहीं उसे भी इंसान ने ही प्रदूषित किया है। बड़ी फैक्ट्रियां बनायीं, ग्रीन हाउस गैसों को निकाला, गाड़ियों से धुआं छोड़ा जो वातावरण में जाकर हवा में मिल गया। दर हक़ीक़त इंसान ने भौतिकवाद और ऐशो-आराम की प्राप्ति के लिए फितरत के ख़िलाफ़ बग़ावत की, पेड़ों, जंगलों को काटा एटम बम और एटमी एनर्जी प्राप्त करने के लिए प्लांट लगाए जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण पैदा होता चला गया।

इसके अलावा ज़िन्दगी के मामलात में भी इंसान ने फितरत के रास्ते से हटने की कोशिश की जिसने इसकी रही-सही ज़िन्दगी को भी पेचीदा बना दिया। समाजी व मआशरती ज़िन्दगी में ग़ैर फितरी कार्यों को क़दम-क़दम देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हया इंसान की फितरत (स्वभाव) में दाख़िल है। विशेष तौर से औरतों में शर्म व हया कूट-कूट कर भरी हुई है लेकिन आज के इंसान ने फितरत के ख़िलाफ़ बग़ावत करते हुए ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि लोग हया के ख़िलाफ़ बग़ावत पर उतर आए और वह औरतें जो शर्म व हया का नमूना थीं उन्होंने हया की चादर को तार-तार कर डाला खुलेआम बाज़ार में आ गयीं, बेहिजाब ग़ैर मर्दों से बेतकल्लुफ़ बातें करने लगीं। परिणाम यह हुआ कि औरतें असुरक्षित हों गयीं और बदमाश, आवारा नौजवानों ने औरतों का पीछा करना शुरू कर दिया और जहां मौक़ा लगा वहां उन्हें हवस का शिकार बना लिया। यहां तक कि सड़कों, पार्कों, घूमने के स्थानों पर औरतों के साथ यौन शोषण किया जाने लगा। राह चलती हुई औरतों को गाड़ियों में खींच लेना और उनके साथ जबरदस्ती करना आम हो गया। (वर्ष 2012 निर्भया कांड) बस के अंदर पांच वहशी नौजवानों के द्वारा एक लड़की का सामूहिक बलात्कार होना फितरत के ख़िलाफ़ एक ऐसा क़दम था जिसने बहुत से इंसानों के दिलों को झकझोर डाला था और वह सड़कों पर आ गए थे। बलात्कारियों के ख़िलाफ़ सख़्त सज़ा की मांग उठ खड़ी हुई। जनता की ज़बरदस्त मांग को देखते हुए सरकार ने दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए फुर्ती दिखाई और अदालत में मुक़दमा चलाया गया। अदालत ने इस केस को शीघ्र निपटाते हुए एक वर्ष से पहले ही सारे सबूत और संबंधित कार्यवाही को पूरा कर लिया और जो लोग इस वारदात में शामिल थे उनके लिए सज़ा- ए-मौत का ऐलान कर दिया। अलबत्ता नाबालिग़ को कुछ साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई। वहशी दरिन्दों के ख़िलाफ़ फैसला आ जाने के बाद लोगों ने इत्मीनान की सांस ली और यह इच्छा व्यक्त की कि अगर इसी तरह वहशियों को सज़ा मिलती रही तो औरतों के यौन शोषण के मामलों-वारदातों में कमी आ सकती है। अदालत के ज़रिए दिया गया बलात्कारियों के ख़िलाफ़ सज़ा-ए- मौत का फैसला एक बेहतरीन फैसला है अब आवश्यकता इस बात की है कि एक तरफ बलात्कारियों के ख़िलाफ़ कानूनी शिकंजा कसा जाए और दूसरी ओर देश के सामाजिक मामलों को साफ-सुथरा बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर प्रभावी तरीके से इंसान को उसकी फितरत की तरफ लाया जाए तो यक़ीनन इंसान शर्म व हया की ओर वापस आ सकता है।

हर शख़्स को चाहिए कि अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएं। अपने घरों में ऐसी चीज़ों को न घुसने दें जो आगे चलकर ख़राब प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए कोशिश की जाए कि अपने घरों को टीवी से अलग रखा जाए क्योंकि इन से बच्चों के कानों के आदी होने का ख़तरा है। घरों में औरतें फैशन और बेजां बनाव- सिंगार से भी बचें। इसलिए कि अगर वह अजीब व ग़रीब डिजाइन कटिंग के कपड़े पहनेंगी तो घर में मौजूद छोटी बच्चियां भी इसी तरह फैशन में दिलचस्पी लेने लगेंगीं।

ठीक यह होगा कि अपने देश की समाजी फिज़ा को बेहयाई से पवित्र रखने के लिए विशेष क़दम उठाए जाएं और इस मामले में पश्चिम का अनुकरण न किया जाए। अय्याशी व बेशर्मी का व्यवहार पश्चिमी देशों में अधिक है इसलिए वहां बलात्कार व बुरे कामों के असंख्य मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, अवैध संतानें पैदा हो रही हैं जिसके कारण इन नन्हीं सी जानों को या तो कूड़े के ढेरों की भेंट किया जा रहा है, या उन्हें बाल आश्रमों में भेजा जा रहा है। यही नहीं बल्कि इस खतरनाक कार्य के कारण आपसी रिश्तों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और पारिवारिक व्यवस्था बिखर रही है। पारिवारिक जीवन निरस साबित हो रहा है। सीमा से अधिक तलाक़ों की घटनाएं सामने आ रहीं हैं। एक पुरुष कितनी ही औरतों से शादी करता है मगर किसी औरत से भी उसका पारिवारिक संबंध अधिक समय तक शेष नहीं रहता। ऐसे ही औरत कई-कई शादियां करती नज़र आती हैं लेकिन उसका पारिवारिक बंधन भी कुछ ही समय के बाद टूट जाता है परिणाम यह कि ज्यों- ज्यों समय गुज़रता जाता है उदासियां निराशा और घृणा घेर लेती है। मानसिक तनाव में बढ़ोत्तरी हो जाती है और उसकी ज़िन्दगी बर्बाद होकर रह जाती है। हमें अपने देश को ऐसे हालात से बचाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे।

समाज का प्रत्येक व्यक्ति फितरत से जुड़ने की कोशिश करे और ग़ैर फितरी मामलों का बायकॉट करे। हर शख़्स को चाहिए कि अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएं। अपने घरों में ऐसी चीज़ों को न घुसने दें जो आगे चलकर ख़राब प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए कोशिश की जाए कि अपने घरों को टीवी से अलग रखा जाए क्योंकि इन से बच्चों के कानों के आदी होने का ख़तरा है। घरों में औरतें फैशन और बेजां बनाव- सिंगार से भी बचें। इसलिए कि अगर वह अजीब व ग़रीब डिजाइन कटिंग के कपड़े पहनेंगी तो घर में मौजूद छोटी बच्चियां भी इसी तरह फैशन में दिलचस्पी लेने लगेंगीं। बहरहाल हर स्थिति में फितरी तक़ाज़ों को पूरा किया जाए और ग़ैर फितरी बातों से बचा जाए।

इस्लाम कहता है कि जब बच्चे जवान हो जाएं तो इनका निकाह कर दिया जाए। इस्लाम यह हुक्म इसलिए देता है कि जवानी के बाद जो तक़ाज़े सामने आते हैं वह निकाह के बाद ठीक तरीक़े से पूरा हो जाते हैं लेकिन जवान होने के बावजूद शादी न करना फितरी तक़ाज़ो की पूर्ति से रुकना है मगर इसके ग़लत परिणाम सामने आते हैं और अवैध व हराम कामों के बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अजीब बात है कि आजकल विवाह शादियों को देर से करने का फैशन बना लिया गया है। 30 साल की उम्र में या इससे अधिक आयु में शादी करने का रिवाज़ आम हो गया है। जबकि इसको बालिग़ हुए बीस साल का समय गुज़र चुका हुआ है। इस बीच में नफ़्स पर कंट्रोल करना हर शख़्स के लिए आसान नहीं होता, इसलिए फितरत के अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारना इंसानियत के हक़ में लाभदायक है और फितरत के अनुसार पूरी ज़िन्दगी गुज़ारने की एक प्रभावी स्थिति यही है कि इंसान दीन-इस्लाम पर पूरी तरह चलने वाला हो जाए, ज़िन्दगी खुद-ब-खुद फितरत के अनुसार गुज़रती रहेगी क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और इंसान की फितरत की तरफ रहनुमाई (मार्ग दर्शन) करता है।❑❑

नवनीत शर्मा

भारत में शिक्षा का अर्थशास्त्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' करना समाज दर्शन की यात्रा न होकर एक अर्थशास्त्रीय विमर्श का भी प्रतिस्थापन है। मनुष्य को संसाधन और शिक्षा को निवेश मानना उस अर्थशास्त्रीय संरचना को इंगित करता है जो किसी भी तरह की सक्षमता को पूंजी की तरह चिह्नित करता है। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नव उदारवाद का वैश्विक स्तर पर फैलाव और सतत् विकास की अनुशंसाओं से युक्त दक्षिण कोरिया के इंचियान घोषणापत्र में सभी सहभागी देशों से उनके सकल घरेलू उत्पाद का चार से छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना अपेक्षित माना गया। भारत ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और 2030 तक शिक्षा को सभी भारतीयों की पहुंच में लाने और शत-प्रतिशत नामांकन के लिए प्रतिबद्ध जताई है। नई शिक्षा नीति का कलेवर हालांकि इससे भिन्न शिक्षा को मात्र निवेश और मनुष्य को संसाधन न मान, इसे आत्म उत्थान, राष्ट्र उत्थान से जोड़कर देखता है। इस नीति को राजनीतिक एजेंडे से अलग कर देखा जाए तो भी यह अपनी जटिलताओं के कारण पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती। इस बार के प्रस्तावित बजट से अपेक्षा थी कि वह अपनी ही सरकार द्वारा निर्मित इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन करेगा, लेकिन 2021-22 का बजटीय प्रावधान इसके उलट न केवल पिछले वर्ष के मुक़ाबले शिक्षायी आवंटन में छह प्रतिशत की कटौती करता है और इस वर्ष के जीडीपी का मात्र पौने तीन प्रतिशत शिक्षा पर ख़र्च करने की योजना प्रस्तुत करता है।

वित्त मंत्री ने विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग पर 54873 करोड़ के बजट की घोषणा की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 4971 करोड़ रुपए यानि 8.3 प्रतिशत कम है। सामान्य शिक्षा पर खर्च को देखें तो यह 15127 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 343 करोड़ रुपए या लगभग सवा दो प्रतिशत कम है। शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अखिल भारत उच्चतर शिक्षा सर्वे (2015-16) रिपोर्ट के अनुसार देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या सात सौ निन्यावें और महाविद्यालयों की कुल संख्या ती लाख उनतालीस हजार इकहत्तर हैं इसमें जिसमें निजी विश्वविद्यालय दो सौ सतहत्तर हैं। इन विश्व विद्यालयों की कुल संख्या तीन लाख उनतालीस हजार इकहत्तर है। इन विश्वविद्यालयों एवं इससे संबंधित महाविद्यालयों की कुल संख्या लगभग साढ़े चौंतीस लाख है जिसमें लगभग साढ़े अठारह लाख लड़के और सोलह लाख लड़कियों का नामांकन है। इन विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या लगभग पन्द्रह लाख है, जिसमें इकसठ प्रतिशत पुरुष और उनतालीस प्रतिशत महिलाएं हैं। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात एक और इक्कीस (1:21) का है। इन्हीं आंकड़ों को आधार बना कर यह कहा जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश काफी तरक्क़ी कर चुका है। लेकिन अठारह से तेईस वर्ष के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर की स्थिति को देखें तो उच्च शिक्षा की यह तस्वीर निराशाजनक है क्योंकि इसी रिपोर्ट के अनुसार अठारह से तेईस वर्ष के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में सकल नामांमन दर 24.5 प्रतिशत है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बहुत बड़ी साक्षर आबादी, जो 48.50 प्रतिशत है, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इस आबादी के उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मज़बूत कारण उच्च शिक्षा में वित्तीय पूंजी का अभाव भी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के शिक्षा मद में बजट आवंटन से समझा जा सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा का कुल बजट लगभग 93,44 करोड़ है जो कुल बजट का लगभग तीन प्रतिशत है। इस बजट में उच्चतर शिक्षा विभाग को 38350 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जो कुल शिक्षा बजट का लगभग इकतालीस प्रतिशत है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा का कुल बजट 99311 करोड़ रुपए था जिसमें उच्चतर शिक्षा विभाग का बजट 39466 करोड़ रुपए था। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से देखें तो शिक्षा बजट में लगभग साढ़े छह प्रतिशत (6,087 करोड़ रुपए) और उच्चतर शिक्षा में लगभग पौने तीन प्रतिशत (1115 करोड़ रुपए) की कमी की गई है।

भारत में 44 केन्द्रीय विश्व विद्यालय और तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। 2021-22 के बजट में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 7643 करोड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 7686 करोड़ का प्रावधान किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आबंटन की गई राशि के मुक़ाबले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 43 लाख करोड़ कम मिले, जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या इनके मुक़ाबले लगभग दोगुनी है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संख्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय प्रबंध संस्थानों की कुल संख्या के बराबर है, लेकिन बजट में इन दोनों संस्थानों के लिए आवंटित की गई कुल राशि 8162 करोड़ रुपए के मुकाबले केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के लिए आवंटित की गई राशि 7643 करोड़ रुपए का अंतर 518 करोड़ रुपए, जो मामूली नहीं है।

भारत में 44 केन्द्रीय विश्व विद्यालय और तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। 2021-22 के बजट में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 7643 करोड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 7686 करोड़ का प्रावधान किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आबंटन की गई राशि के मुक़ाबले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 43 लाख करोड़ कम मिले, जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या इनके मुक़ाबले लगभग दोगुनी है।

कोई भी वित्तीय आवंटन गत वर्ष में हुए ख़र्च के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। गत वर्ष शिक्षा के लिए 99 हज़ार करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसमें से शिक्षा मंत्रालय मात्र 85 हजार करोड़ रुपए ही खर्च कर सका। यह एक महत्वपूर्ण तर्क है कि यदि शिक्षा जिसे जीडीपी का सवा तीन प्रतिशत आवंटित किया गया और वह खर्च नहीं हो पाया तो शिक्षाविद् जीडीपी के छह प्रतिशत की गुहार क्यों करते हैं। खर्च नहीं हो पाया और खर्च नहीं हो सकता के बीच भिन्न व्यवस्थाएं काम करती हैं। शिक्षा का पर्याप्त संस्थायीकरण और मौजूदा सांस्थानिक ढांचों की कार्यशैली मं आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्तियां (अध्यापक एवं अन्य कर्मियों की) की जाएं, छात्रवृत्ति के आवंटन को बढ़ाकर अधिक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाए, ग़ैर-नेट शोधार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता दी जाए, संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्ता दी जाए, विज्ञान, समाज विज्ञान एवं अन्य विषयों के लिए अन्याय, भाषाओं में पाठ सामग्री तैयार की जाए और स्कूली ढांचों का सुधार एवं निर्माण हो इत्यादि। ऐसे अनेक सुझाव लगभग सभी शिक्षा समितियों और नीति निर्माताओं ने दिए हैं। अब इन्हें सिर्फ अमली जामा पहनाने की ज़रूरत बची है।

इस बजट को यदि मानवीय अभिप्रेरणाओं के अब्राहीम मेस्लो की आवश्यकताओं की वरीयता पर कसा जाए तो अलग ही दृश्य बनता है। इसके लिए कुल बजट राशि को कुल जनसंख्या से विभाजित कर के समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए रक्षा मद को आवंटित पौने पांच लाख करोड़ की राशि को यदि एक सौ इक्कीस करोड़ की आबादी से विभाजित करें तो हम प्रति व्यक्ति चार हज़ार रुपए (सुरक्षा) पर कर रहे हैं। इसी तरह प्रति व्यक्ति कृषि पर ग्यारह सौ, स्वास्थ्य पर छह सौ दस रुपए और शिक्षा हेतु प्रति व्यक्ति सात सौ सत्तर रुपए खर्च कर रहे हैं। मैस्लो के अनुसार, हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद (सुरक्षा) संबंधी चिंताएं करते हैं। शिक्षायी आवंटन को यदि और विस्तार से देखें तो प्रत्येक स्कूली छात्र छात्रा पर राज्य इक्कीस सौ और प्रत्येक उच्च शिक्षा के छात्र छात्रा पर ग्यारह हजार रुपए ख़र्च कर रहे हैं। शिक्षा के निजीकरण के पक्षधर इस बात को भी समझें कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति विद्यार्थी लगभग तेरह हजार डॉलर ख़र्च करता हैं शिक्षा का यह अर्थशास्त्र किस तरह का भविष्य गर्भ में लिए हुए है, इसका संकेत न्यायमूर्ति पुन्नैया समिति और स्वामीनाथन पैनल की रिपोर्ट में है, जिसके अनुसार जो अकथ्य है और अवश्यंभावी है, वह है फीस का बढ़ना, फीस बढ़ोत्तरी से सर्वाधिक प्रभावी होने वाले हाशिये के लोग जैसे अल्पसंख्यक, दलित और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और शायद इस 'उत्कृष्टता' की दौड़ में और पिछड़ जाएं। ❑❑

ख़ास ख़बरें

उत्तर कोरिया ने किया लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण

सियोल : अमेरिका के साथ 2019 से जारी गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि इस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि इस क्रूज मिसाइल ने करीब 1,500 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर सटीक वार किया। इसे उत्तर कोरिया ने रणनीतिक हथियार बताते हुए बेहद अहम करार दिया है।

नाइजीरियाई जेल में बंदूकधारियों ने किया हमला, 240 क़ैदी फरार

अबुजा : नाइजीरिया की एक जेल में भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस दौरान जेल में बंद 240 क़ैदी फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान जेल में कुल 294 क़ैदी थे। फिलहाल नाइजीरिया के सुधार महानियंत्रक हलिरू नबाबा को हमले की जांच की ज़िम्मेदारी दी गई।

अमेरिका में मोटी रक़म देकर आसानी से पा सकेंगे ग्रीन कार्ड

वाशिंगटन : अमेरिका में एक विधेयक के पारित होने से भारतीयों सहित लाखों लोगों को पूरक शुल्क का भुगतान करके ग्रीन कार्ड (स्थायी निवासी कार्ड) हासिल करने में मदद मिल सकती है। देश में रोज़गार आधारित ग्रीन कार्ड का सालों से इंतज़ार कर रहे बड़ी संख्या में भारतीयों समेत लाखों लोग पूरक शुल्क का भुगतान करके अमेरिका में वैध स्थायी निवास पा सकते हैं। यदि इसे सुलह समझौता पैकेज में शामिल कर कानून में पारित किया गया तो हज़ारों आईटी पेशेवरों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

चीन ने कहा, सभी पक्ष संयम बरतें

बीजिंग : उत्तर कोरिया के मित्र चीन ने मिसाइल परीक्षण पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की हे। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने केवल सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने, उसी दिशा में आगे बढ़ने, सक्रिय रूप से बातचीत में शामिल होने और राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए संपर्क करने का आग्रह किया है। जबकि उत्तर कोरिया ने कहा है कि मिसाइलों का विकास देश की सुरक्षा को अधिक भरोसेमंद बनाने की गारंटी देता हैं। जानकार बताते हैं कि मिसाइलों का परीक्षण करना उत्तर कोरिया की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, वह खुद पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को ख़त्म करने के लिहाज़ से अमेरिका पर वार्ता का दबाव बनाने को लेकर भी ऐसे परीक्षण करता रहा है।

ग़ैर मुस्लिमों के साथ रहमतुललिल आलमीन का सद्व्यवहार

सैयद कमरूल हसन

छठी सदी इंसानी इतिहास का एक ऐसा अंधकारमय दौर गुजरा है जिसमें पूरी मानवता तबाही के दोहाने पर पहुंच चुकी थी। दुनिया के सारे बड़े धर्म और उनके नियम व कानून और धार्मिक पुस्तकें इस बेदर्दी और बेरहमी के साथ परिवर्तन का शिकार हो चुके थे और इनकी हकीक़त व सूरत को इस कदर समाप्त के बदला जा चुका था कि इनके असली रूप को पहचानना न सिर्फ मुश्किल बल्कि असंभव हो रहा था।

कुफ्र, शिर्क, बुतपरस्ती, अशिक्षा, चोरी डकैती, लूटमार, झूठ, क़त्ल व ग़ारतगरी बेरहमी, दंगा फसाद जुल्म बर्बरता, शराब नोशी, ऐशपरस्ती, स्वार्थ, हवस, अधिकारों का हनन, आर्थिक शोषण और कौन सा ऐसा ऐब व बुरायी नहीं थे। ऐसा महसूस होता था कि पूरी मानव जाति खुदकुशी पर आमादा और हलाकत के दहाने पर खड़ी हुई हैं इंसान इंसानियत को ख़ाक में मिला रहा है। संस्कृति अपनी सीमा से हट गयी है और यह मसला किसी एक कौम या एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानव जाति और उसके भविष्य का था। अल्लाह तआला इसी हक़ीक़त को फरमाते हैं। (सूरह आल इमरान) अनुवाद : ''तुम लोग आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे खुदा ने तुमको इससे बचा लिया।''

पूरा समाज, नैतिक और समाजिक पिछड़ेपन का शिकार था। अज्ञानता इस सीमा तक इंसानी ज़िन्दगी में रच बस चुकी थी कि पूरी ज़िन्दगी बिखर कर रह गयी थी। हर ओर एक घनघोर अंधेरा और गहरी निराशा थी। इतिहास के इस बुरे दौर में इंसानियत और आदमियत के भविष्य और उसकी तरक्की (बक़ा) के मार्ग में निराशा के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता था। इन हालात में अल्लाह को अपनी मख़्लूक (लोगों) पर रहम आया और उसने उस वरिष्ठ इंसान को अपना रसूल बनाकर भेजा जिसका नाम नामी इस्में गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम है। इरशाद हुआ (सूरत अल अम्बिया) ''और (ऐ मोहम्मद) हमने तुमको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम रहमतुललिल्ल आलमीन बनाकर भेजे गए तो आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने इसका हक अदा कर दिया। इंसान के जीवन चर्या के लिए उच्च स्तरीय नैतिक और रूहानी आदर्शों को आधार क़रार दिया। यह जीवन गुज़ारना हमारी व्यक्तिगत सामूहिक जिन्दगी में कशमकश टकराव की संभावनाओं का सम्पूर्ण ख़ात्मा करके सारे इंसानों के बीच पूरी तरह मानसिक एक रूपता और व्यवहारिक सहयोग कार्यविधि का न सिर्फ मज़बूत रिश्ता क़ायम करने वाला बना बल्कि हमारे अंदर आपसी हमदर्दी व क़ुर्बानी की रूह भी जागृत की। क़ुरान करीम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की सबसे बड़ी सिफ्त (गुण) इसी अख़्लाक को करार देते हुए कहता है ''(सूरज तुल नून) अनुवाद ''ऐ रसूल (सल्ल॰) बेशक आप अख़्लाक के बड़े पद पर विद्यमान हैं।

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने इस्लाम की प्रशंसा करते हुए फरमाया ''यानि आला और अच्छे अख़्लाक़ को अपनाना ही दरअसल इस्लाम है।

खल्क़ अज़ीम और आला अख़्लाक़ का भावार्थ तो यह है कि अपने हों या पराए, दोस्त हों या दुश्मन इंसान हों, या हैवान सबके साथ अच्छे, शरीफाना और बेहतरीन अख़्लाक़ व सुलूक का प्रदर्शन किया जाए। मख़्लूक खुदा के साथ मौहब्बत और रहमदिली से पेश आया जाए। इनकी खताओं से दरगुज़र किया जाए और बिना शक रसूल अकरम की ज़ात मुबारक खल्क़ अज़ीम की इस कसौटी पर सौ प्रतिशत खरी उतरती है।

इस्लाम और हादी इस्लाम का यह परिचय बता रहा है कि इस्लाम की शिक्षाओं में खुदा की मख़्लूक के साथ बुलंद अच्छे अख़्लाक और अच्छे व्यवहार के साथ पेश आने और जिन्दगी गुज़ारने की सम्पूर्ण हिदायतें मौजूद हैं। यहां बुरे अख़्लाक़ और बुरे बर्ताव की कोई जगह नहीं हैं। ''खल्क़ अज़ीम'' क्या है। अपने ख़ानदान अपनी औलाद अपने दोस्तों और अपने संबंधितों के साथ मोहब्बत से पेश आना और अच्छा बर्ताव करना हर इंसान का तबअी और अखलाकी तक़ाज़ा होता है। हम इस बर्ताव को जो ''अपनों'' के साथ तबई तौर पर किया जाता है ख़ल्क अज़ीम से ताबीर नहीं कर सकते। खल्क़ अज़ीम और आला अख़्लाक़ का भावार्थ तो यह है कि अपने हों या पराए, दोस्त हों या दुश्मन इंसान हों, या हैवान सबके साथ अच्छे, शरीफाना और बेहतरीन अख़्लाक़ व सुलूक का प्रदर्शन किया जाए। मख़्लूक खुदा के साथ मौहब्बत और रहमदिली से पेश आया जाए। इनकी खताओं से दरगुज़र किया जाए और बिना शक रसूल अकरम (सल्ल॰) की ज़ात मुबारक खल्क़ अज़ीम की इस कसौटी पर सौ प्रतिशत खरी उतरती है।

नबूवत का शुरूआती दौर है। आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मक्का की एक गली से गुज़र रहे हैं। इस्लाम दुश्मन और बुग्ज़ व अदावत की मारी एक काफ़िर औरत पर नज़र पड़ती है। वह घर का कूड़ा करकट जमा करती और मकान की ऊपरी मंजिल से आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पर उड़ेल देती है। आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम अपने कपड़ों को झाड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। औरत इस हरकत को अपना मामूल (नित्यक्रम) बना लेती है। आप (सल्ल॰) जब कभी भी उधर से गुजरते वह अपनी नफरत और दुश्मनी का इजहार इसी तरह करती। एक दिन यह बड़ी हस्ती जिसे अल्लाह ने रहमतुललिल आलमीन के लक़ब से नवाज़ा था जब उधर से गुज़रे तो आदत के अनुसार आप (सल्ल॰) पर कूड़ा नहीं फेंका गया। नबी रहमत को फिक्र हुई। तहकीक से पता चला कि वह मुश्रिक औरत बीमार है। आप बेचैन हो गए और अयादत के लिए इस के घर जा पहुंचे। एक दुश्मन के साथ आपके इस हुस्ने सुलूक और अख्लाक करीमाना का प्रभाव यह हुआ कि औरत मुसलमान हो गयी।

आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम अख़लाक के सम्पूर्ण महान व्यक्तित्व थे और यकीन हुस्ने अख़लाक का सम्पूर्ण नमूना। कुरआन का इरशाद है (सूरह अहज़ाब) ''दरहकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) में एक बेहतरीन नमूना हैं।

हज़रत आली करमअल्लावजहा ने आपके संबंध से फरमाया कि आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम बिल्कुल बदकलामी और बेहयाई व बेशर्मी से दूर थे। बुराई का बदला बुराई से न देते किसी पर कभी दस्तदराजी न फरमाते। मैंने जब तक अल्लाह तआला की निर्धारित सीमाओं की ख़िलाफवर्ज़ी न हो, आपको किसी जुल्म व ज्यादाती का इंतकाम (बदला) लेते हुए भी नहीं देखा।

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल अलक़ नं॰ 96)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

जिसने आदमी को लहू से बनाया।

जमा हुआ खून, जिसमें न चेतना न बुद्धि न ज्ञान और न समझ-बूझ। केवल जड़ पदार्थ है, वह जो अल्लाह ऐसे जड़ पदार्थ को बुद्धि वाला इंसान बना देता है, फिर क्या वह एक बुद्धिमान को कामिल, अनपढ़ इंसान को पढ़ने वाला और विद्वान् नहीं बना सकता? यहां तक पढ़ने की संभावना को सिद्ध करना था कि अल्लाह को कुछ कठिन नहीं कि तुमको अनपढ़ होते हुए भी पढ़ने वाला बना दे। आगे पढ़ने वाला बना डज़लने की सूचना देते हैं।

आप पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है।

अर्थात् आपका पालन-पोषण जिस शान से किया गया, उससे आपका पूर्ण व्यक्तित्व उभरेगा और उसका विकास होगा। जब इधर से योग्यता में कमी नहीं, तो उधर से कृपा दृष्टि में कंजूसी नहीं बल्कि वह तमाम दयावानों से बड़ा दयावान है, फिर कृपा प्राप्त करने में क्या वस्तु रुकावट हो सकती है। आवश्यक है कि यूं ही होकर रहे।

जिसने क़लम से शिक्षा दी।

हज़रत शाह साहब लिखते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ ने कभी लिखा पढ़ा न था, कहा कि कलम से भी शिक्षा वही देता है, यूं भी वही देगा और संभव हैं इधर भी संकेत हो कि जिस प्रकार लाभ प्राप्त करने वाले और लाभ देने वाले के बीच क़लम माध्यम होता है उसी प्रकार अल्लाह और मुहम्मद के बीच जिब्रील (वह्यी लाने वाला फरिश्ता) केवल एक माध्यम है जिस प्रकार कलम का माध्यम होने का यह मतलब नहीं कि वह लाभ प्राप्त करने वाले से ऊंचा हो जाये। ऐसे ही यहां जिब्रील अलै॰ का हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ से बढ़िया या ऊंचा होना अनिवार्य नहीं होता।

इंसान को उन वस्तुओं की शिक्षा दी जिनको वह जानता न था।

अर्थात् इंसान का बच्चा मां के पेट से पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, तत्पश्चात् उसको धीरे-धीरे कौन सिखाता है। बस वही अल्लाह जो इंसान को अनपढ़ से पढ़ा-लिखा बनाता है। अपने एक बिना पढ़े को ब्रह्मज्ञानी ही नहीं बल्कि अल्लाह जो इंसान को अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाता है। अपने एक बिना पढ़े को ब्रह्मज्ञानी ही नहीं बल्कि तमाम ब्रह्मज्ञानियों का सरदान बना देगा।

सचमुच निःसंदेह आदमी सीमा से बढ़ जाता है। इस कारण कि अपने आप को बेपरवाह देखता है।

अर्थात् आदमी की वास्तविकता तो केवल इतनी है कि जमे हुए खून से बना और बुद्धू था, अल्लाह ने ज्ञान दिया मगर वह अपनी वास्तविकता को तनिक याद नहीं रखता। दुनिया के माल दौलत पर घमंडी होकर उद्दण्डता करने पर तुल जाता है और समझता है मुझे किसी की परवाह नहीं।

(ऐ मनुष्य) तेरे रब ही की ओर सबका लौटना होगा।

अर्थात् अव्वल भी उसने पैदा किया आख़िर भी उसी के पास लौटकर जाना है। उस समय इस घमंड और अपने आपको भुला देने की वास्तविकता खुलेगी।

ऐ आदमी भला उस व्यक्ति का तो हाल बता जो एक बंदे को बंदे को रोकता है जब वह नमाज़ पढ़ता है।

अर्थात् इसके विद्रोह और घमंड को देखो स्वयं को अपने रब के सामने सज्दे का सौभाग्य नहीं, दूसरा व्यक्ति अगर अल्लाह के सामने सज्दा करता है उसे भी नहीं देख सकता। इन आयतों में आपके दुश्मन (अबु जहल की ओर संकेत है) जब वह हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ को नमाज़ पढ़ते देखता था तो चिढ़ाता और धमकाता था और भिन्न-भिन्न रूप से कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता था।

नअ्त शरीफ़

दिलों के गुलशन महक रहे हैं ये कैफ़ क्यों आज आ रहे हैं
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हैं

कहां का मंसब कहां की दौलत क़सम खुदा की ये है हक़ीक़त
जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीना को जो रहे हैं

हबीबे दावर ग़रीब परवर रसूले अकरम करम के पैकर
किसी को दर पर बुला रहे हैं किसी के ख़्वाबों में आ रहे हैं

न पास पी हो तो सूना सावन वो जिस पर राज़ी वही सुहागन
जिन्होंने थामा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं

नवाज़िशों पे नवाज़िशें हैं इनायतों पे इनायते हैं
नबी की नअ्तें सुना सुनाकर हम अपनी क़िस्मत जगा रहे हैं

बनेगा जाने का फिर बहाना कहेगा आकर कोई दीवाना
चलो नियाज़ी तुम्हीं मदीने, मदीने आक़ा बुला रहे हैं।

राजनीति में जब बादल गरते हैं, बरसते नहीं

आलोक मेहता

एक बुज़ुर्ग राजनेता ने 1983 में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हुए मुझे विदुर नीति की यह सूक्ति सुनाई थी कि

'सचिव, बैद, गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस।

राज, धर्म, तनु तीनि कर होइ बेगिहिं नास।'

यानि यदि भय के कारण, सचिव, चिकित्सक और गुरु मनपसंद मीठी बातें कहते हैं, तो निश्चित रूप से विनाश होता है। चालीस वर्ष बाद भी आज राजनीति में यह स्थिति दिखाई दे रही है। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी इस संकट से गुज़र रही है। इंदिरा, राजीव गांधी काल में ऐसे कई नेता सहयोगी होते थे और कड़वी बातें सुना देते थे। लेकिन जब खुशामदी नेताओं और सहायकों पर निर्भरता हुई तो सत्ता और संगठन चरमराने लगा। नेतृत्व जब केवल बादल की तरह ऊंचाई से गरजते रहें और ज़मीन को राहत देने, उसे हरा भ्रा करने के लिए स्वयं

वर्तमान दौर में तो अजीब स्थिति है, राहुल गांधी ने पूर्व अध्यक्ष का तमगा लगा लिया, लेकिन किसी अन्य नेता को कार्यकारी अथवा उपाध्यक्ष बनाकर संगठन को मजबूत नहीं किया। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष भले ही हों, निर्णय तो राहुल की मनमानी से होते हैं।

जमकर नहीं बरसे तो सफलता के सपने कैसे साकार हो सकते हैं। राहुल गांधी के अनिर्णय और राज्यों में असंतोष और विफलताओं से कांग्रेस आज 1977 से अधिक कमज़ोर दिखाई दे रही है।

राहुल गांधी और उनके सहयोगी कम्प्यूटर के आंकड़ों से दुकान चलाने वाले बाहरी लोगों के बजाय सिर्फ इंदिरा गांधी द्वारा 1969 से लेकर 1983 तक अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए फार्मूलों को भी अपना लेते तो उनकी इतनी दुर्गति नहीं दिखाई देती। 1977 में पराज्य के बाद भी उन्होंने ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अर्स को आगे रखा। 1980 में भारी बहुमत से सत्ता मिली, लेकिन दो वर्ष बाद ही दक्षिण भारत के विधान सभा चुनावों में पराज्य का मुंह देखना पड़ा और उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों के असंतोष के साथ संगठन कमज़ोर दिखने लगा। तब 1983 के प्रारंभ में उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया, ताकि संगठन को सुदृढ़ किया जा सके। मैंने तब भी अपने विश्लेषण में लिखा था कि इंदिरा गांधी ने इस कदम से स्वीकार किया कि दक्षिण की पराज्य केवल प्रादेशिक नेतृत्व की क्षमता ही उत्तरदायी नहीं है, वरन वे स्वयं भी ज़िम्मेदार हैं।

वर्तमान दौर में तो अजीब स्थिति है, राहुल गांधी ने पूर्व अध्यक्ष का तमगा लगा लिया, लेकिन किसी अन्य नेता को कार्यकारी अथवा उपाध्यक्ष बनाकर संगठन को मजबूत नहीं किया। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष भले ही हों, निर्णय तो राहुल की मनमानी से होते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने दो पीढ़ियों को साथ रखने, उन्हें आगे रखने के प्रयास जब तक किए उन्हें प्रदेशों में सरकारें और संगठन को मजबूत रखने में सुविधा हुई। आलोचकों की सुनने के बाद आवश्यक सुधार करने में उन्हें हिचक नहीं होती। कांग्रेस संगठन की कमज़ोरी पर इन्दिरा गांधी को किसी बेहद नाराज़ और अलग हो चुके नेता से सलाह लेने का एक उदाहरण मुझे फरवरी 1983 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र से उनकी लंबी मुलाक़ात से मिला था। इस भेंट के बाद मिश्रजी ने न केवल इन्दिरा गांधी को पूरी साफगोही से कही गई बातों का उल्लेख किया, उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति भी दे दी। मिश्रजी से मेरा परिचय 1972 से था। उन्हें कांग्रेस का चाणक्य माना जाता था। आपातकाल और कुछ अन्य निर्णयों से दुखी होकर वह पार्टी से दूर से हो गए थे।

बहरहाल 82 वर्षीय पंडित द्वारका मिश्रजी ने तब मुझसे कहा –'कांग्रेस के प्रति अब भी मेरी सहानुभूति है और उसकी हालत देखकर तकलीफ़ होती है। वास्तव में कई सालों से पार्टी के चुनाव नहीं हुए। हर जिले में कुछ लोग हैं जो अपनी पसंद न होने पर समर्थन कर देते हैं और पसंद न होने पर उसे पराजित करने में अपनी ताक़त लगा देते हैं। कांग्रेस का संगठन कहां रह गया है – सब कुछ ऊपर ही ऊपर है, निचले स्तर पर तो कोई है ही नहीं।' इस कड़वी सच्चाई को सुनने के बाद ही श्रीमति गांधी ने कमलापति त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ नेताओं और राजीव गांधी जैसे युवाओं को साथ में काम करने के लिए लगाया।

लेकिन एक डेढ़ वर्ष में उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी ने भी दो तीन साल इस संतुलन को निभाया। लेकिन अरुण नेहरू जैसे सहयोगियों ने बुज़ुर्गों को अपमानित किया और बाद में खुद सत्ता की जड़ें खोद दी। राहुल गांधी की नई माडर्न टीम वही काम कर रही है। तभी तो कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, अशोक गहलौत, भूपेष

इंदिरा युग के चाणक्य कहे जाने वाले द्वारका प्रसाद मिश्र, कामराज और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे नेता इस विशेषण को ग़लत कहते थे। डॉक्टर शर्मा ने एक बार अनौपचारिक बातचीत में मुझे कहा था –'हमें बहुत बुरा लगता है, जब हमारी तुलना चाणक्य से की जाती है और चाणक्य की तुलन मेकवेले से की जाती है।

बघेल के साथ मनीष तिवारी, सचिन पायलट, टी.एस. सिंहदेव, की फजीहत सार्वजनिक रूप से हो रही है। इस संदर्भ में हाल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हरवाने वाले चुनावी लॉबिस्ट पी.के. को इन दिनों कांग्रेस के लिए चाणक्य की भूमिका मिलने पर असली कांग्रेस आसूं बहा रहे हैं। इंदिरा युग के चाणक्य कहे जाने वाले द्वारका प्रसाद मिश्र, कामराज और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा (राजीव राज तक) जैसे नेता इस विशेषण को ग़लत कहते थे। डॉक्टर शर्मा ने एक बार अनौपचारिक बातचीत में मुझे कहा था –'हमें बहुत बुरा लगता है, जब हमारी तुलना चाणक्य से की जाती है और चाणक्य की तुलन मेकवेले से की जाती है। वास्तव में चाणक्य महर्षि थे।

मेकेवेले से उनकी तुलना अपमान है। मेकेवेले ने तो एक किताब लिखी 'प्रिंस' और उसे लेकर कई रियासतों में बंटी इटली में घूम-घूम कर खूब पैसा इकट्ठा किया। चाणक्य तो महार्षि

बाक़ी पेज 11 पर

बिहार – जद (यू०) में नंबर दो की लड़ाई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल-यूनाइटेड के निर्विवाद नेता हैं। उनके नेतृत्व पर प्रश्न उठाने वाला दूर-दूर तक कोई नहीं हैं, इस पर पार्टी में अंदरूनी जंग चल रही हैं। जहां नीतीश सहयोगी पार्टी भाजपा पर नियंत्रण बहाल करने के लिए रणनीतियां तैयार करने में लगे हुए हैं, जद (यू) के वरिष्ठ नेताओं की एक तिकड़ी अपने-अपने तरीक़े से संगठन में खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करने में लगी हुई है, जिसमें केन्द्रीय इस्पात मंत्री आर.सी.पी. सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा और जद (यू.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह शामिल हैं।

ये तीनों नेता एक दूसरे को शह और मात देने में व्यस्त हैं। पूर्व आइएएस अधिकारी आरसीपी को दो दशकों से मुख्यमंत्री के प्रति सबसे वफादार माना जाता है। कुशवाहा और ललन की गणना भी उनके करीबी नेताओं में होती है, इसके बावजूद कि अतीत में दोनों के साथ मुख्यमंत्री के कटु मतभेद भी रहे हैं। फिलहाल, तीनों नेताओं ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जद-यू को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन राजनीतिक महत्वकांक्षाओं के चलते उनके बीच खींचतान जारी है। लिहाज़ा, वे अलग-अलग बैठकों, रैलियों और यात्राओं के ज़रिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसकी शुरुआत इस वर्ष जुलाई में नरेन्द्र मोदी सरकार में जद-यू के एकमात्र मंत्री के रूप में आरसीपी के शपथ लेने के बाद हुई। माना जा रहा था कि आरसीपी और ललन दोनों को केन्द्रीय मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आरसीपी को मौक़ा मिला। जदयू से केवल एक मंत्री बनाया जाना आश्चर्य से कम नहीं था क्योंकि नीतीश ने 2019 के आम चुनाव के बाद जदयू को एक मंत्री पद की पेशकश ठुकरा दी थी।

ललन ने आरसीपी पर परोक्ष रूप से दोष मढ़ने की कोशिश की, क्योंकि तब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, 'यह पार्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। 2019 में केन्द्रीय मंत्रालय में शामिल नहीं होने का निर्णय तब लिया गया था जब नीतीश कुमार अध्यक्ष थे।' इशारा यह था कि आरसीपी ने पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक मंत्री पद स्वीकार किया।

आरसीपी ने कहा कि सब कुछ नीतीश की सहमति से हुआ है। उन्होंने जोर दिया कि वे पार्टी अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री की दोहरी ज़िम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं लेकिन, नीतीश ने ललन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर मानो प्रतिद्वंद्वी खेमों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया।

पार्टी में अंदरूनी कलह तब खुलकर सामने आई जब अगस्त में ललन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से पटना लौटे। उस दौरान किसी भी पोस्टर या बैर में आरसीपी की तस्वीरें नहीं दिखीं। दस दिन बाद, जब आरसीपी केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली से पटना आए तो उनके समर्थकों ने ललन को पार्टी के पोस्टर और बैनर पर जगह नही दी।

अंदरूनी कलह का एक तीसरा कोण भी है। ये हैं उपेन्द्र कुशवाहा, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जद-यू में विलय कर दिया था और वे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनको जद-यू का राष्ट्रीय अध्क्ष बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन ललन अध्यक्ष बनाए गए। कुशवाहा उसके बाद से राज्यव्यापी दौरा कर रहे हैं और उनके समर्थकों ने उन्हें कुछ जगहों पर भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं।

इस बीच नीतीश ने पार्टी में कलह से इंकार किया है। उनका कहना है कि ललन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में किया था। ललन भी कहते हैं ''जदयू में सिर्फ एक खेमा है – नीतीश खेमा और हम सब पार्टी को बिहार में फिर से नंबर 1 बनाने को प्रतिबद्ध है। हालांकि विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि जद-यू में सत्ता के लिए घमासान चल रहा है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि उपेन्द्र कुशवाहा ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पार्टी का जदयू में विलय किया था। वे कहते हैं 'वे जद-यू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह ऐसा पद है जो पार्टी संविधान में मौजूद ही नहीं है।

लोजपा अध्यक्ष चिराग़ पासवान कहते हैं कि जद-यू विभाजन की ओर बढ़ रहा है, 'पार्टी में हर खेमा अपने वर्चस्व में जुटा है। इसकी वजह से नीतीश सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं करने वाली है और बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है।' ❑❑

घरेलू सरज़मीं पर चार टैस्ट, तीन वनडे और 14 टी/20 खेलेगा भारत

भारतीय क्रिकेट टीम नवंबर 2021 से जून 2022 के बीच घरेलू सरज़मीं पर चार टैस्ट, 14 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय और महज़ तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आठ माह के इस अवधि में न्यूजीलैंड (नवंबर-दिसंबर) वेस्टइंडीज (फरवरी 2022), श्रीलंका (फरवरी-मार्च 2022) और दक्षिण अफ्रीका (जून 2022) की टीमें भारत का दौरा करेंगी।

इस बीच भारतीय टीम दिसंबर 2021 - जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी और अप्रैल-मई (2022) में इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ दो टेस्ट और तीन टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी जबकि वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ उसे तीन एकदिवसीय और पांच टी-20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने हैं। श्रीलंकाई टीम भारत के दौरे पर दो टेस्ट और तीन टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम का भारतीय दौरा हालांकि महज़ 10 दिनों का होगा जिसमें उसे पांच टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि हमने 14 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय इसलिए रखे हैं क्योंकि एक वर्ष के अंदर आस्ट्रेलिया में एक और विश्व कप होना है। उस बड़े आयोजन से पहले हमें पर्याप्त संख्या में मैच खेलने की आवश्यकता है। चार टैस्ट मैचों में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ दो मुक़ाबले कानपुर और मुंबई में खेले जाएंगे जबकि श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैचों की मेज़बानी बंगलुरु और मोहाली को सौंपी गई है। रोटेशन नीति के तहत सीमित ओवरों के 17 मैचों के स्थल का चयन किया गया है जिसमें जयपुर, रांची, लखनऊ, विशाखापट्टनम, कोलकाता, अहमदाबाद, कटक, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, राजकोट, दिल्ली को मेज़बानी का मौक़ा मिलेगा।

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़

17 नवंबर : पहला टी-20 (जयपुर)
19 नवंबर : दूसरा टी-20 (रांची)
21 नवंबर : तीसरा टी-20 (कोलकाता)
25 से 29 नवंबर : पहला टैस्ट (कानपुर)
तीन 3 से 7 दिसंबर: दूसरा टैस्ट (मुंबई)

श्रीलंका के ख़िलाफ़

25 फरवरी-1 मार्च : पहला टैस्ट (बंगलुरु)
5 से 9 मार्च : दूसरा टेस्ट (मौहाली)
13 मार्च : पहला टी-20 (मोहाली)
15 मार्च : दूसरा टी-20 (धर्मशाला)
18 मार्च : तीसरा टी-20 (लखनऊ)

द० अफ्रीका के ख़िलाफ़

9 जून : पहला टी-20 (मुंबई)
12 जून : दूसरा टी-20 (बंगलुरु)
14 जून : तीसरा टी-20 (नागपुर)
17 जून : चौथा टी-20 (राजकोट)
19 जून : पांचवां टी-20 (दिल्ली)

वेस्टींडीज के ख़िलाफ़

6 फरवरी : पहला वनडे (अहमदाबाद)
9 फरवरी : दूसरा वनडे (जयपुर)
12 फरवरी : तीसरा वनडे (कोलकाता)
15 फरवरी : पहला टी-20 (कटक)
18 फरवरी : दूसरा टी-20 (विजाग)
21 फरवरी : तीसरा टी-20 (त्रिवेन्द्रम)

क्रिकेटरों को 50 फीसद अतिरिक्त मैच फीस मिलेगी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने कोविड के कारण कम अवधि का कर दिए गए 2020-21 सत्र से प्रभावित घरेलू क्रिकेटरों के लिए मुआवज़े के तौर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त मैच फीस की घोषणा की। इसके साथ ही आगामी सत्र के लिए शुल्क में बढ़ोत्तरी भी की। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो पाया था जिससे कई भारतीय क्रिकेटरों को वित्तीय परेशानियों से जूझना पड़ा। इन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआइ के मुआवज़े की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बीसीसीआइ के सचिव जय शाह ने टवीट करके कहा, 'जिन क्रिकेटरों ने 2019-20 के घरेलू क्रिकेट सत्र में हिस्सा लिया था उन्हें 2020-21 सत्र के लिए मुआवज़ा के तौर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त मैच फीस दी जाएगी।' मुआवज़ा देने और मैच में बढ़ोत्तरी करने का फैसला बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद की बैठक में किया गया। जिन रणजी खिलाड़ियों ने 40 से अधिक मैच खेले हैं उनकी मैच फीस लगभग दोगुनी 60 हज़ार रुपए प्रतिदिन हो गई है जिसका मतलब है कि खिलाड़ी एक मैच से दो लाख 40 हजार रुपए कमा सकते हैं। जिन खिलाड़ियों ने 21 से 40 मैच खेले हैं उन्हें प्रतिदिन 50 हज़ार रुपए जबकि इससे कम अनुभव रखने वाले क्रिकेटरों को प्रतिदिन 40 हज़ार रुपए मिलेंगे। बीसीसीआइ के इस क़दम से अंडर-16 से लेकर सीनियर स्तर तक लगभग 2000 क्रिकेटरों को लाभ मिलेगा।

अंकुरित भोजन से रहें फिट एंड फाइन

शाकाहार का पूरा-पूरा लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने भोजन को कम से कम पकने दें या फिर उन्हें उबाल कर खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा देर तक पकाने से व्यंजन स्वादिष्ट ज़रूर पकता है किन्तु उनके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। समय एवं ईंधन की बर्बादी अलग होती है।

अधिकांश कन्दमूल, फल एवं साग हम कच्चे खाते हैं। पत्ता गोभी, ककड़ी, गाजर, मूली और प्याज़ से बनाए जाने वाला सलाद शरीर में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करता है। अंकुरित अन्न केवल स्वास्थ्यवर्धक ही नहीं, बल्कि रोगनाशक सजीव भोजन है। अंकुरित अन्न खाने से रोगों की संभावनाएं काफी कम होती हैं और मनुष्य स्वस्थ्य जीवन जीते हुए दीर्घायु प्राप्त करता है।

अंकुरित अन्न बनाने की विधि

देशी चना, साबुत मूंग, लोबिया या मटर, कच्ची मूंगफली या तिल, गेहूं या सोयाबीन आदि अन्नों को शीत एवं ग्रीष्मऋतु में निम्न रूप से अंकुरित कर सकते हैं। जिन अन्नों को अंकुरित अन्न बनाना है उन्हें प्रात: पानी में भिगोकर ढंक कर रख दें। शाम को पानी से निकाल कर उस अन्न को किसी बंद डिब्बे में या फिर मोटे कपड़े की पोटली में बांधकर रख दें। अगले दिन अंकुरित अन्न खाने के लिए तैयार मिलेगा।

अंकुरित अन्न खाने की विधि

आईये, अब थोड़ी चर्चा अंकुरित अन्न को अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर कैसे खाएं, इस संदर्भ में कर लें।

- सादा पानी और अंकुरित अन्न।
- शहद और अंकुरित अन्न।
- सेंधा नमक और अंकुरित अन्न।
- गुड़ और अंकुरित अन्न।
- कच्ची खांड और अंकुरित अन्न।
- फल और अंकुरित अन्न।

मट्ठा और अंकुरित अन्न।

सब्ज़ियों के जूस अथवा सूप के साथ अंकुरित अन्न

- कढ़ी और अंकुरित अन्न।
- केला और अंकुरित अन्न।
- हल्की भाप में अंकुरित अन्न।
- बेलगिरी और अंकुरित अन्न।
- आम और अंकुरित अन्न।।
- पपीता और अंकुरित अन्न।

अंकुरित अन्न में पौष्टिक तत्व पूर्ववत् रहते हैं। यही वजह है कि अंकुरित अन्न का सेवन करने वाले जीने के लिए खाते हैं और न कि खाने के लिए खाते हैं। अत: अच्छा यही होगा कि हम अपने बच्चों में अंकुरित अन्न के सेवन की आदत डालें। फास्ट फूड की आदत छुड़ाएं, क्योंकि 'फास्ट फूड' से मोटा पर बढ़ता है।

हर दिन एक डोज हड्डियों के लिए

एक उम्र के बाद हड्डियों में कैल्शियम का संचित भंडार कम होने लगता है। यही वजह है कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं। विशेषकर महिलाओं में यह समस्या आम है। मेनोपोज के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन नामक हारमोन कम होने लगते हैं। इस दौरान महिलाओं में अनेक शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जिनमें हड्डियों का कमजोर होना भी एक है। लेकिन इससे बचाव हो सकता है, अगर शुरू से ही हड्डियों की देखभाल की जाए। हड्डियों की सेहत के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :-

मेनोपॉज होने के पहले खासकर 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं के प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से युक्त डाइट लेनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त हेल्थ ड्रिंक भी लिया जा सकता है। कैल्शियम युक्त डाइट जैसे दूध, मछली, हरी सब्जियां दही, सोयाबीन, टोफू आदि खाने में शामिल करें। खाने के अलावा आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकती हैं, पर इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से ज़रूर सलाह लें।

केवल कैल्शियम की गोली खाने से इस बीमारी से निजात नहीं मिल पाएगी। इसके साथ आपको विटामिन डी भी ज़रूरी है। दरअसल, शरीर में कैल्शियम आब्जार्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की ज़रूरत के लिए चाहिए सूर्य की रेशनी। रोजाना सुबह धूप में बीस मिनट बैठने से शरीर को आवश्यकता के अनुसार विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा आप सालमोन मछली, अंडा आदि खाएं। लहसुन और प्याज भी नियमित खाएं। ये सल्फर के अच्छे स्रोत होते हैं। नियमित व्यायाम के साथ शारीरिक गतिविधियां जारी रखें। व्यायाम करने से हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। सप्ताह में 2-4 बार वजन उठाने वाले व्यायाम करें। इससे मांसपेशिया मजबूत होती हैं और हड्डियां भी स्वस्थ रहती हैं। पैदल चलना, जॉगिंग करना, डांस करना, जिम जाना, सीढ़ियां चढ़ना, योग या हल्के फुल्के व्यायाम करके भी हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है।

स्टेरॉयड और रक्त को पतला करने वाली दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। इन दवाइयों का सेवन करना भी पड़े, तो डाक्टर की सलाह पर निर्धारित खुराक से अधिक नहीं लें।

शराब और धूम्रपान का सेवन न करें

खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफी या चाय से परहेज़ करें, क्योंकि इनसे हड्डियों में संचित कैल्शियम को नुकसान पहुंचता है। हाई प्रोटीन मांस का सेवन भी ज़्यादा न करें, क्योंकि इससे शरीर से कैल्शियम कम होने लगता है।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2001 से 2014 तक देश में 2,290 महिलाओं की हत्या डायन बता कर पीट-पीट कर की गई। इनमें 464 हत्याएं अकेले झारखंड में हुईं। ओडिशा में 415 और आंध्र प्रदेश में ऐसी 383 हत्याएं हो चुकी हैं। इसी क्रम में हरियाणा में 209 हत्याएं हुई हैं। स्टेप्स फाउंडेशन के अनुसार 28 सितंबर, 2015 से 07 जून, 2019 तक घटी ऐसी घटनाओं में 141 लोगों की जान जा चुकी हैं इसमें मरने वालों में 70 मुस्लिम और 71 गैर मुस्लिम हैं। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि भीड़ की नज़र में न तो कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान, भीड़ समान रूप से सभी को अपना शिकार बनाती है। 2018 में सबसे ज़्यादा 61 लोगों की हत्या हुई। इसलिए सबसे पहले इन घटनाओं को धार्मिक नज़र से देखने के बजाय सामाजिक विकृति और संविधान की मूल भावना के विपरीत रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये तमाम आंकड़े बेहद गंभीर और चिंतनीय स्थिति की ओर इशारा करते है। ❑❑

शेष.... अफ़ग़ानिस्तान....

साथ राजनयिक संबंध स्थापित करें।

तालिबान को अपनी सरकार चलाने के लिए फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मदद की आवश्यकता है। चार दशक के लंबे संघर्ष से इस देश की हालत खस्ता है। अमेरिकी समर्थन से चल रही पिछली सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद पर आश्रित थी। पिछले दिनों तालिबान के सत्ता पर काबिज़ होने से पहले अफग़ानिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी। अब नए निज़ाम में हालात और बिगड़ रहे हैं। ग़रीबी अचानक बढ़ने लगी है। तालिबान इस हालात को बहुत चिंताजनक नहीं मानता है।

प्रवक्ता ने कहा कि हम बग़ैर विदेशी मदद के अपना काम चला सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। हमने अब तक जो देखा और समझा है उसके मुताबिक अफग़ानिस्तान आर्थिक रूप से नाकाम देश नहीं है। हमारे पास पर्याप्त राजस्व है। हम इसे ठीक से नियंत्रित और जमा करते हैं तो हम अपनी सभी तात्कालिक समस्याएं हल कर लेंगे। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र जिस देश की 97 प्रतिशत प्रतिशत आबादी के वर्ष के अंत तक गरीबी रेखा के नीचे जाने का अनुमान लगा रहा है उससे राजस्व कैसे जुटाया जाएगा।

तालिबान ने अपनी कैबिनेट को अंतरिम सरकार का नाम दिया है लेकिन अब तक यह साफ नहीं किया कि देश में आगे कभी चुनाव होंगे या नहीं। तालिबान सरकार में फिलहाल एक से कक्षा छह तक की छात्राओं को स्कूल आने की इजाज़त मिली है। ❑❑

शेष.... अगर कैप्टन साढ़े चार साल...

का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा.?

जवाब:- कांग्रेस को लूटर ही मान कर चलिए। वह चाहे जो भी जतन कर ले, पॉवर में लौटने वाली नहीं है।

सवाल:- कहा तो यह जा रहा है कि कैप्टन को हटाने के बाद अब कांग्रेस एंटी इनकंबेंसी फैक्टर से बच जाएगी?

जवाब:- अगर साढ़े चार वर्ष के शासन में कैप्टन जनता से किए वादों को पूरा करने में विफल रहे, उनको लेकर जनता में नाराज़गी है तो उसके लिए केवल कैप्टन नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी ज़िम्मेदार है। जनता की जितनी नाराज़गी कैप्टर से है, उतनी ही कांग्रेस से भी है। कैप्टन को हटाकर कांग्रेस बच जाएगी, यह नहीं सोचा जा सकता। ❑❑

शेष.... राजनीति में जब बादल...

थे और मौर्य साम्राज्य में उनकी उपलब्धि थी। वह गंगा के उस पार रहते थे और किसानों द्वारा फसल काटने के बाद बचे अनाज को इकट्ठा कर अपना पेट भर लेते थे। उन्हें सत्ता से किसी लाभ की अपेक्षा नहीं थी। अब पी.के. हों या कोई अन्य क्या भारतीय राजनीति में कोई चाणक्य कहलाने लायक़ समर्पित व्यक्ति है?

मेरे मीडिया के योग्य मित्रों को भी किसी को चाणक्य लिखते बोलते समय सोचना चाहिये। महर्षि का नाम क्यों ख़राब किया जाए। वर्तमान राजनीतिक दौर में बरजने गरजने कड़ी बात कहने सुनने वालों की संख्या शायद कम होती जा रही है। इसके बिना लोकतंत्र की जड़ें भी सूखने लगेंगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के मज़बूत होने और अनेक राज्यों में सत्ता में रहने से विचलित कई नेता और कुछ नामी विशेषज्ञ इस स्थिति को खतरनाक बता रहे हैं। वे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के सर्व शक्तिमान् होने से भी परेशान हैं लेकिन अनुभवी पुराने नेताओं और पत्रकारों को अस्सी के दशक के उन दावों और तर्कों को याद दिलाना चाहिये, जिनके आधार पर लिखा जाता था कि केन्द्र के मजबूत रहने से देश अधिक सुरक्षित और विकसित हो सकता है। भारत का प्राचीन इतिहास भी इस बात का प्रमाण है कि जब भी केन्द्र की सत्ता कमज़ोर हुई है, विभिन्न रियासतों के सूबेदारों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी।'

आज भी विभिन्न राज्यों की सरकारें होने पर केवल राजनीतिक टकराव ही नहीं हो रहा, अविश्वास और कभी-कभी अराजकता की स्थिति दिखने लगती है। जनहित वाली योजनाएं अमल में नहीं लाई जा रही, जांच एजेंसियों और प्रादेशिक पुलिस प्रशासन में सीधे टकराव, गिरफ्तारी की नौबत आ गई है। क्षेत्रीय भावना और अस्तित्व की पहचान एक हद तक समझी जा सकती है, लेकिन संघीय स्वरूप में बेहतर तालमेल, विश्वास, सम्मान होने पर ही समाज राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। ❑❑

शेष.... ग़ैर मुस्लिमों के साथ...

आप (सल्ल॰) लोगों की दिलदारी फरमाते किसी भी कौम व बिरादरी का सम्मानीय व्यक्ति आता तो उसके साथ एजाज व इकराम का मामला फरमाते अच्छी बात की अच्छाई बयान फरमाते और उसको ताकत पहुंचाते आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम सबसे अधिक फराख़ दिल सहृदय सद्व्यवहारी नरम तबीअत और मआशत व मआमलात में निहायत दर्जा करीम थे। गैर मुस्लिमों के साथ आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के हुस्न सुलूक और ऊफू व दरगुज़र की रिवायतों से हदीस की मुस्तनद किताबें भरी पड़ी हैं। आप सल्ल॰ ने साफ साफ फरमाया। अनुवाद ''इंसान खुदा का कुन्बा है और खुदा को अपने बन्दों में सबसे ज्यादा महबूब वह है जो इसके कुन्बे के साथ अच्छा अख़्लाक करे।

(मिश्कात बरवायत बेहकी)

अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया अनुवाद ''तुम अहले ज़मीन पर रहम खाओगे तो वह ज़ात जो आसमानों में है तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगी। हाली ने इस हदीस का मन्जूम तर्जुमा इन शब्दों में किया है।

करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर
खुदा मेहरबां होगा अर्श बरीं पर।

आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम अपनी बाअश्त का मकसद और अपनी सारी दावत व तब्लीग का असली मिशन ही अख़्लाक की तकमील बताते हैं। इरशाद होता है (मसनद अहमद) अनुवाद ''मैं अख़्लाक हुस्ना की तकमील के लिए भेजा गया हूं।''

एक यहूदी जैद इब्ने सअना ने आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से अपने कर्ज़ की मांग की जो आप (सल्ल॰) ने उससे लिया था अंदाज बहुत सख़्त और बर्बर था (आपके कंधे मुबारक पर पड़ी हुई चादर ज़ोर से खींच कर गोया हुआ कि तुम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद बड़े टाल-मटोल करने वाले लोग हो। हज़रत उमर (रज़ि॰) मौजूद थे आप से बर्दाश्त न हुआ और उसे झिड़कते हुए सख्त लहजे में बात की लेकिन रसूल अल्लाह (सल्ल॰) मुस्कुराते रहे और हज़रत उमर (रज़ि॰) से फरमाया उमर हम और यह आदमी तुम्हारी तरफ से दूसरे रवैये के पात्र थे । मुझे तुम कर्ज जल्दी अदा करने को कहते और उसको नरम लहज़े में तकाज़ा करने को कहते। फिर आपने फरमाया भी इसकी अदायगी के वक्त में तीन दिन शेष हैं। आपने हज़रत उमर को इसके कर्ज़ की अदायगी का हुक्म फरमाया और साथ में बीस साअ इसको अधिक देने को कहा कि यह इसका मुआवज़ा है जो उमर ने इसको खौफज़दा कर दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का यह हुस्ने सुलूक और अख्लाक करिमाना जैद इब्ने सआना के कबूल इस्लाम का कारण बना।

सही बुखारी में है कि नजद की तरफ लश्कर (फौजी) कार्यवाही के दौरान हम सब लोग एक जगह आराम कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम भी एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे। आप (सल्ल॰) ने अपनी तलवार उसी पेड़ पर लटका दी थी। अचानक आपने हमें आवाज दी हम हाज़िर हुए तो देखा कि एक आराबी आप (सल्ल॰) के सामने बैठा हुआ है। आपने फरमाया कि मैं सो रहा था मेरी आंख खुली तो देखा कि यह शख्स मेरे सिर पर मेरी तलवार खींचे खड़ा है। और पूछ रहा है कि तुम्हें मुझ से कौन बचा सकता है। मैंने कहा अल्लाह! इसने तलवार म्यान में कर ली। और बैठ गया। लो यही वह व्यक्ति है। रावी हजरत जाबिर (रज़ि॰) बयान फरमाते हैं कि आपने इसको सजा न दी।

मुशरीकीन मक्का की मुखालफत और अत्याचार जब बहुत अधिक हो गये तब आप इस उम्मीद पर तायफ पहुंचे कि वहां के लोग दीन हक की दावत पर ''लब्बैक'' कहेंगे। लेकिन वहां आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। तायफ में आपको जितना सताया गया वह मुशरीकीन मक्का के बर्बर अत्याचारों से कहीं अधिक था। आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम पर इस क़दर पत्थर बरसाए गए कि आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम जख्मों से लहूलुहान हो गए। खूंन बह-बह कर आपकी एड़ियों में पहुंच रहा था। और जूते खूंन से लतपत हो गए थे। अत्याधिक बेकसी और कर्ब के आलम में पनाह लेने के लिए आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम एक बाग में एक खजूर के साए में तशरीफ फरमा हुए आपकी जुबान पर अपने आप दुआइया शब्द जारी हो गए और आप सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम अल्लाह तआला से अपनी कमज़ोरी तथा सम्मान की फरियाद करते हुए अल्लाह की मदद और समर्थन के ख़्वाहिशमन्द हुए। अल्लाह को अपने हबीब (सल्ल॰) की इस हालत पर रहम आया उसने पहाड़ों के फरिश्ते को आपके पास भेजा। फरिश्ते ने आपसे कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को जिनके बीच तायफ स्थित है इस तरह मिला दूं कि पूरी कौम इसके अंदर पिस कर रह जाए लेकिन रहमतुललिल आलमीन को यह गंवारा न हुआ कि उन्हें सजा दी जाए। आपने फरमाया ''नहीं मुझे आशा है कि इनकी औलाद में कोई ऐसा अवश्य पैदा होगा जो खुदा तआला की इबादत करेगा और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएगा। (जाद अल मआद जि॰1 सफा 302) ❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

पर दिल्ली एनसीआर के लिए राहत की बात है। आयोग की ओर से साझा कि गए इन राज्यों के विंटर एक्शन प्लान के मुख्य बिंदुओं में पराली प्रबंधन के लिए बायो डि-कंपोजर के इस्तेमाल में इन राज्यों की सहमति का प्रमुख रूप से उल्लेख है। प्लान में एनसीआर के शहरों से संबंधित राज्यों में इंटेलिजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने के लिए टास्क फोर्स के गठन, लैंडफिल साइटों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और धूल नियंत्रण पर खास जोर देने की बात भी कही गई है।

दिल्ली यूँ तो वर्षभर वायु प्रदूषण से जूझती रहती है, लेकिन सर्दी के दिनों में एनसीआर के शहरों में भी गैस चैंबर जैसी स्थिति बन जाती हैं दिल्ली में वर्ष दर वर्ष इस तरह की स्थिति बनना क़तई अस्वीकार्य है। इसके लिए दिल्ली सरकार के साथ ही केन्द्र सरकार व केन्द्रीय स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन यह निराशाजनक है कि अब तक इसका ठोस हल नहीं निकल पाया है। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई बायो डिकंपोजर तकनीक को विभिन्न एजेंसियां पराली जलाने से रोकने के लिए बेहतर विकल्प मान रही है, ऐसे में अब इसके इस्तेमाल के प्रति संबंधित राज्यों में आम राय बन जाने को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तकनीक का प्रयोग बेहतर तरीक़े से होगा और उसका लाभ इसी वर्ष से नज़र आने लगेगा।

योगी के गृह जिले गोरखपुर में कानून व्यवस्था की हालत गंभीर

गोरखपुर में कानपुर के एक कारोबारी की हत्या के करीब 72 घंटे बाद एक मॉडल शराब की दुकान पर काम करने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति को ग्राहकों ने नशे में पीट-पीट कर मार डाला। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित मनीष प्रजापति मध्य प्रदेश का रहने वाला था और पिछले कुछ महीनों से इस मॉडल शराब की दुकान में काम कर रहा था। 1 30 सितम्बर को कुछ लोग दुकान पर आए और शराब का आर्डर दिया। आर्डर मिलने में हो रही देरी से ग्राहक नाराज हो गए और इस पर मनीष के साथ गाली-गलौज भी हो गई। बहस जल्द ही लड़ाई में बदल गया और ग्राहकों ने कथित तौर पर मनीष और एक अन्य स्टाफ सदस्य रघु पर हमला किया। ग्राहकों ने अपने कुछ और दोस्तों को भी बुलाया जो हमले में शामिल हुए और यह लगभग 20 मिनट तक जारी रहा। पुलिस के आने तक हमलावर भाग चुके थे।

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **26 Sep.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•न्याय की गति•पुलिस का चेहरा •सकारात्मक संकेत

न्याय की गति

संसाधनों की कमी की वजह से अगर न्यायाधिकरणों का कामकाज बाधित होता है तो इसे केवल लापरवाही का मामला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह सरकार की कमज़ोर इच्छाशक्ति का भी सबूत है। न्याय प्रक्रिया की जटिलता को आसान बनाने और उस पर बोझ को कम करने के लिए अर्ध न्यायिक संस्थाओं के रूप में न्यायाधिकरणों का ढांचा खड़ा किया गया था। कई स्तरों पर इसके सकारात्मक नतीजे भी देखें गए। लेकिन आज हालत यह है कि इन न्यायाधिकरणों में बड़ी तादाद में ख़ाली पड़े पदों पर

किसी भी सरकार के लिए शीर्ष अदालत की तरह की इस तरह की टिप्पणी असहज कर देने वाली होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बने रहने के बावजूद इस ओर कोई ठोस पहल करना संबंधित महकमों को ज़रूरी नहीं लग रहा है। प्रश्न है कि क्या सरकार संसाधनों की कमी और ज़रूरी नियुक्तियों के अभाव का न्यायाधिकरणों के कामकाज पर पड़ने वाले असर से अंजान है?

नियुक्ति नहीं किए जाने की वजह से इनके कामकाज में बाधा आ रही है। ये न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारियों न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अलग- अलग न्यायाधिकरणों के ज़िम्मे जो काम होगा, वह किस पैमाने पर बाधित हो रहा होगा जबकि इस तरह का तंत्र गठित किए जाने के बाद सरकार को अपनी ओर से सक्रिय और संवेदनशील होकर इसके बेहतर नतीजों का दायरा निर्मित करना चाहिए था, ताकि जनता और संबंधित पक्षों का इस पर भरोसा क़ायम रह सके। मगर इसके प्रति सरकारी उदासीनता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है।

यह स्थिति न समूचे तंत्र के लिए अच्छी है, न इससे सरकार की छवि बेहतर होती है। लेकिन सरकार को यह ख़्याल रखना चाहिए था कि इस संदर्भ में कम से कम वह अदालत के रुख़ पर गंभीरता दिखाती। यह बेवजह नहीं है कि इस मसले पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने अपना सख़्त रवैया दिखते हुए साफ लहज़े में कहा कि केन्द्र सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्ति नहीं करके नहीं करके इन अर्ध न्यायिक संस्थाओं को 'शक्तिहीन' कर रही है। अदालत ने कहा कि वह केन्द्र सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहती, मगर चाहती है कि बड़ी संख्या में रिक्तियां की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में केन्द्र कुछ नियुक्तियां करे। दरअसल, किसी भी सरकार के लिए शीर्ष अदालत की तरह की इस तरह की टिप्पणी असहज कर देने वाली होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बने रहने के बावजूद इस ओर कोई ठोस पहल करना संबंधित महकमों को ज़रूरी नहीं लग रहा है। प्रश्न है कि क्या सरकार संसाधनों की कमी और ज़रूरी नियुक्तियों के अभाव का न्यायाधिकरणों के कामकाज पर पड़ने वाले असर से अंजान है?

ग़ौरतलब है कि अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करने वाले न्यायाधिकरण सेवा मामले, टैक्स, पर्यावरण पर प्रशासनिक फैसलों या वाणिज्यिक क़ानून आदि से जुड़े मामलों का निपटारा करते है। मौजूदा समय में 19 न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य विशेषज्ञों की भागीदारी और तत्परता से फैसले करके न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित करना है। मगर हालत यह है कि पिछले करीब चार वर्ष से किसी भी न्यायाधिकरण में नई न्यायिक नियुक्ति नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जैसे कई अपीलीय न्यायाधिकरण में लगभग ढाई सौ पद ख़ाली पड़े हुए हैं। शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधिकरणों के कामकाज के सुचारु संचालन के लिए बार-बार दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, लेकिन सरकार को उन पर अमल करना ज़रूरी नहीं लगता। अदालत जब भी इस मसले पर सरकार से प्रश्न करती है तो यह जवाब देकर अपना दायित्व पूरा मान लिया जाता है कि नियुक्ति का काम प्रक्रिया में है। पिछले दिनों अदालत ने सरकार को न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए दस दिन का समय दिया था लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी अदालत में सरकार को कोई उचित जवाब दे सकने की दशा में नहीं है।

पुलिस का चेहरा

पुलिस के कामकाज को लेकर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। इसके बावजूद दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा दिल्ली पुलिस का चेहरा काफी हद तक बेदाग़ माना जाता रहा है। उसके कामकाज की मिसाल दी जाती रही है। मगर पिछले कुछ सालों में उसने भी कई संवेदनशील मामलों में जिस तरह पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रहग्रस्त होकर कार्रवाईयां की, उससे उसकी साख को गहरा धक्का लगा है। पिछले वर्ष साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की निष्पक्ष जांच करने और वास्तविक दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उसने कई निर्दोष लोगों को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया। उन दंगों के पीछे साज़िश और उसमें संलिप्त लोगों की पहचान उसी से हो गई थी, जब नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ चल रहे आंदोलनों के विरोध में कुछ नेताओं ने ज़हरीले भाषण दिए और लोगों को उकसाने का प्रयास किया। मगर दिल्ली पुलिस ने उनकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अनेक निर्दोष लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया हालांकि उनमें से कई लोग अब निर्दोष साबित हो चुके हैं, पर अब भी कई मामलों में सुनवाई चल रही है। उन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए अदालतों ने न सिर्फ बार-बार दिल्ली पुलिस के कामकाज पर अंगुली उठाई, बलिक उसे कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई।

एक अदालत ने तो यहां तक कहा कि यह बंटवारे के बाद देश की राजधानी में हुए सबसे ख़राब सांप्रदायिक दंगे थे। मगर इसकी निष्पक्ष जांच के बजाय पुलिस ने अदालत की आंख पर पट्टी बांधने का प्रयास और सार्वजनिक धन का अपव्यय किया। आने वाले पीढ़ियां जब इतिहास पलटेंगी, तो इन दंगों के बारे में जानकर पीड़ा से भर उठेंगी। मगर लगता नहीं कि इन फटकारों का दिल्ली पुलिस पर कोई असर होने वाला है या इन दंगों के असली दोषियों की पहचान उजागर होने वाली है। अदालतें पुलिस की जांचों के आधार पर ही न्याय कर पाती हैं, अगर पुलिस ही साक्ष्य पेश करने में बेईमानी करे, तो न्याय प्रक्रिया बाधित होती है इसलिए अदालतों की पुलिस को फटकार का मतलब समझा जा सकता है। मगर पुलिस की विवशता भी किसी से छिपी नहीं हैं वह अपनी कार्यशैली बदलने का प्रयास करना भी चाहे तो उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब सरकारों के इशारे पर काम करना जैसे उसकी विवशता है।

हालांकि पुलिस सुधार के लिए गठित तमाम समितियों ने बार-बार सुझाया है कि पुलिस का चेहरा बदलने की ज़रूरत है। पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। अधिकारियों को कम से कम दो वर्ष तक एक जगह तैनात रखा जाए। उनका बार-बार तबादला न किया जाए। मगर केन्द्र की किसी भी सरकार ने उन सुझावों पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए कि सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करती रही है। अगर वे पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए छोड़ देंगी, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी। राजनीतिक दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की पैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। सत्तापक्ष अपने करीबी लोगों के अपराध और अपनी अनियमितताओं पर पर्दा डालने में तभी सफल हो सकती है, जब वह पुलिस को अपने चंगुल में रखे। इसलिए सरकारें पुलिस अधिकारियों को तरह-तरह के शिकंजों में जकड़ कर रखने का प्रयास करती हैं। दिल्ली पुलिस पर वह शिकंजा अब शायद कुछ अधिक कस गया है, इसीलिए वह वही करती देखी जाती है, जो सरकार चाहती है।

सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करती रही है। अगर वे पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए छोड़ देंगी, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी। राजनीतिक दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की पैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। सत्तापक्ष अपने करीबी लोगों के अपराध पर पर्दा डालने में तभी सफल हो सकती है

सकारात्मक संकेत

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के दिनों में गहराने वाले वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के प्रयासों में तेजी आना स्वागतयोग्य है। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ने खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए बायो डिकंपोजर तकनीक अपनाने पर हामी भर दी है, जो निश्चित तौर

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173